www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 08 | गोरखपुर, 17 अगस्त 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

मुख्यमंत्रियों की बैठक संपन्न

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गत शनिवार को अपने मेघालय समकक्ष कोनराड के संगमा से यहां मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज गुवाहाटी में मेरी मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड के संगमा के साथ चर्चा हुई। हमने दोनों राज्यों की साझा प्रगति को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों मुख्यमंत्रियों की पिछली मुलाकात दो जून को हुई थी, जिसमें स्वतंत्रता दिवस तक 12 विवादित क्षेत्रों में से पांच पर सीमा स्तंभ स्थापित करने पर सहमति बनी थी। असम और मेघालय ने मार्च 2022 में छह क्षेत्रों के सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सीमा स्तंभ पांच क्षेत्रों में लगाने पर सहमति बनी थी, जबकि छठे क्षेत्र पिलिंगटा को लेकर व्याख्या में अंतर होने के कारण वहां फिलहाल निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के उपायुक्तों के स्तर पर चर्चा होनी थी। वर्ष 1972 में असम से अलग कर मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस दौरान असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को मेघालय ने चुनौती दी थी, जिसके चलते 884.9 किलोमीटर लंबी सीमा पर 12 क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न हुआ।

▶ अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि

'सदैव अटल' पहुंचे राष्ट्रपति और पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके स्मारक ह्यसदैव अटलह्ल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राजघाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई अन्य गणमान्य लोग वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उनके स्मारक सदैव अटल पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सातवीं पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सभी को प्रेरित करते रहेंगे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ह्यहमसभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे। वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में मात्र 13 दिनों का था। इसके बाद, वह 1998 में फिर प्रधानमंत्री बनें और उन्होंने 13 महीने तक इस पद को संभाला। वर्ष 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। वायपेयी को आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जिससे देश का तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील करके कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़े हैं मोदीः राउत

नई दिल्ली। शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने गत शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेशी का समर्थन करके असली कांग्रेसी बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया और दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया स्वदेशी का नारा कांग्रेस का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले यह नारा दिया था और यह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी दृष्टिकोण था। शिवसेना (उबाठा) के नेता ने कहा, आज फिर से यह नारा देकर, मोदी गांधी और नेहरू के रास्ते पर चल पड़े हैं। वह एक असली कांग्रेसी बन गए हैं।

प्लास्टिक सामान निर्माण इकाई में आग लगी, पांच की मौत

- घटना केआर मार्केट के नागरथपेट क्षेत्र की।
- आग बुझाने के लिए आठ वाहन लगाए गए हैं और 55 दमकलकर्मी तथा 21 अधिकारी मौके पर मौजूद

बेंगलुरु। बेंगलुरु के के.आर. मार्केट के पास नागरथपेट क्षेत्र में प्लास्टिक का सामान बनाने की एक इकाई में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने मृतकों की पहचान मदन सिंह (38), संगीता (33) और उनके दो बच्चों रितेश (7) और विहान (5) तथा पड़ोसी सुरेश कुमार (26) के रूप में की है। पुलिस के अनुसार, मदन सिंह राजस्थान के मूल निवासी थे और लगभग 10 सालों से इस इमारत को किराए पर ले रखा था। वह एक छोटी फैक्टरी चलाते थे जहां प्लास्टिक के सामान के साथ-साथ चटाई भी बनायी जाती थी। वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते थे। पुलिस ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह करीब तीन बजकर 14 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए आठ वाहन लगाए गए हैं और 55 दमकलकर्मी तथा 21 अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, यह एक तरह का गोदाम है जहां काफी सामान रखा हुआ है। इस वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत शहर के घनी आबादी वाले कारोबारी इलाके में स्थित है।

निर्वाचन आयोग विपक्ष के आरोपों के बीच आज संवाददाता सम्मेलन करेगा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच निर्वाचन आयोग (ईसी) रविवार को संवाददाता सम्मेलन करेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक तौर पर संवाददाता सम्मेलन बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है।

संवाददाता सम्मेलन का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है। राहुल गांधी ने बार-बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया है, साथ ही एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी होगी। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, उन्हें शामिल न करने के कारणों सहित, प्रकाशित करने को कहा है।

हत्या के मामले में फरार आरोपी नौ साल बाद गिरफ्तार

पुणे। पालघर जिले में 2016 के हत्या के एक मामले में विरार पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहां एक अधिकारी ने गत शनिवार को यह जानकारी दी। विरार अपराध शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक शाहूराज राणावरे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले सोनू अच्छेलाल गुप्ता (35) को कई महीनों की गहन जांच के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। यहां 30 अक्टूबर 2016 को हुए एक विवाद के बाद कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले से संबंधित एक मामले में गुप्ता कथित रूप से शामिल था। इस हमले में सोनू परशुराम झा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी दो सप्ताह बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। निरीक्षक ने बताया कि गुप्ता उस समय ठाणे के ओवाला इलाके में रहता था और घटना के बाद वह फरार हो गया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता आंदोलन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में अज्ञानता से घिरे लोग अकसर यह प्रश्न पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही है? कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि संघ के किसी एक कार्यकर्ता का नाम ही बता दीजिए, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो? संघ की स्थापना जिन्होंने की, वे डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार स्वयं ही जन्मजात देशभक्त थे। डॉ. हेडगेवार क्रांतिकारी भी रहे, कांग्रेस में रहकर राजनीतिक संघर्ष किया और जेल भी गए। बाद में, देश की सर्वांग स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉ. हेडगेवार अकेले नहीं हैं, अपितु स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेनेवाले संघ के ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ताओं की लंबी शृंखला है। जो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को यह शपथ दिलाता हो कि मैं हिन्दूराष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ, उसने कितने ही लोगों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव भरा होगा, उसकी सहज कल्पना की जा सकती है।

भारत में प्रतिज्ञा का बहुत महत्व है। हमें भीष्म प्रतिज्ञा का स्मरण है। राजा हरिशचंद्र की सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ध्यान है। मुगलिया सल्तनत के अत्याचार के विरुद्ध महाराण प्रताप की प्रतिज्ञा को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करके ह्यस्वराज्यह्ल की नींव रखी, जिसे साकार करने में संपूर्ण समाज प्राणपण से जुट गया। संघ के स्वयंसेवक भी इसी भाव के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि वह जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसको पूर्ण करने में अपना सर्वस्व देंगे और प्रतिज्ञा को आजन्म निभाएंगे। मार्च 1928 में नागपुर के निकट एक पहाड़ी पर स्वयंसेवकों को एकत्र करके, भगवाध्वज के समक्ष प्रतिज्ञा का पहला कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया था। देश की पूर्ण स्वतंत्रता एवं विकास के लिए स्वयंसेवकों को वीरव्रती बनाने के निमित्त आयोजित इस प्रथम कार्यक्रम में 99 स्वयंसेवकों ने प्रतिज्ञा की थी। इस अवसर पर डॉ. हेडगेवार ने संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए जो भाषण दिया, वह स्वतंत्रता प्राप्ति की संघ की आकांक्षा को स्पष्टतौर पर व्यक्त करता है। उन्होंने कहा- ह्लहमारा उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र की पूर्ण स्वाधीनता है। संघ का निर्माण इसी महान लक्ष्य के लिए हुआ हैह्ल। इस स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद कहने के लिए कुछ और भी बचता है क्या? यह भी समझना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपनी नित्य प्रार्थना में कहते हैं कि इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है। क्या कोई पराधीन राष्ट्र परम वैभव पर जा सकता है? स्पष्ट है कि भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य संघ की स्थापना में निहित था।

डॉक्टर साहब ने 1929 में वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में भी स्वयंसेवकों एवं नागरिकों की एक सभा में प्रखरता के साथ कहा- ह्लब्रिटेन की सरकार ने अनेक बार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया है, परंतु वह झूठा साबित हुआ। अब यह साफ हो गया कि भारत अपने बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करेगाह्ल। याद रहे कि डॉ. हेडगेवार ने महात्मा गांधी के आह्वान पर ह्यनमक सत्याग्रहह्ल में शामिल होकर विदर्भ प्रांत में 1930 में ह्यजंगल सत्याग्रहह्ल किया। इस आंदोलन में उनके साथ अनेक प्रमुख स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सत्याग्रहियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। डॉक्टर साहब को नौ माह का कठोर कारावास दिया गया। इससे पूर्व 1921 के आंदोलन में भी डॉक्टर साहब को जेल की सजा हुई थी। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मध्यभारत में सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों ने अथक प्रयास किया। संघ के सरकार्यवाह जीएम हुद्दार, नागपुर के संघचालक अप्पा साहेब हलदे, सिरपुर के संघचालक बाबूराव वैद्य, संघ के सरसेनापति मार्तंडराव जोग के साथ संघ के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं के आंदोलन में शामिल होने के कारण चार-चार माह का कारावास मिला।

अपनी स्थापना के कई वर्षों बाद कांग्रेस को जनमानस के दबाव के कारण 31 दिसंबर, 1929 को लाहौर में रावी के तट पर पहली बार ह्यपूर्ण स्वराज्यह्ल का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। याद रहे कि डॉ. हेडगेवार ने 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास किया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए। बहरहाल, सम्पूर्ण स्वतंत्रता का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। कांग्रेस का यह निर्णय संघ के घोषित उद्देश्य के अनुरूप था। इसलिए इससे आनंदित होकर सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करने, राष्ट्रध्वज का वंदन करने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी कहा कि शाखाओं पर भाषण करके स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ एवं महत्व को समझाया जाए। सरसंघचालक के निदेर्शानुसार, संघ की सभी शाखाओं पर 26 जनवरी, 1930 को सायं 6 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

संघ के स्वयंसेवकों ने 1942 के अंग्रेजो, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सहभागिता की। 8 अगस्त, 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान पर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधीजी ने आंदोलन की घोषणा की। दूसरे दिन से ही देशभर में आंदोलन प्रारंभ हो गया। विदर्भ में बावली (अमरावती), आष्टी (वर्धा) और चिमूर (चंद्रपुर) में हुए आंदोलनों में संघ के स्वयंसेवकों ने ही नेतृत्व किया। चिमूर के समाचार बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित हुए। यहां के आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारी दादा नाईक, बाबूराव बेगडे, अण्णाजी सिरास ने किया। चिमूर के इस आन्दोलन में अंग्रेज की गोली से एकमात्र मृत्यु बालाजी रायपुरकर की हुई, जो संघ स्वयंसेवक थे। इस आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान में प्रचारक जयदेवजी पाठक, आर्वी (विदर्भ) में डॉ. अण्णासाहब देशपांडे, जशपुर (छत्तीसगढ़) में रमाकांत केशव (बालासाहब) देशपांडे, दिल्ली में वसंतराव ओक एवं चंद्रकांत भारद्वाज और पटना (बिहार) में अधिवक्ता कृष्ण वल्लभप्रसाद नारायण सिंह (बबुआजी) ने भाग लिया।

अंग्रेज सरकार संघ के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई थी। इसलिए उसने संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए ताकि संघरूपी आंदोलन को रोका जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले 15 दिसंबर, 1932 को एक सर्कुलर निकालकर सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं, 5 अगस्त, 1940 को ब्रिटिश सरकार ने संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया।क्योंकि सरकार को गुप्तचर रिपोर्ट में यह जानकारी मिलने लगी थी कि संघ के स्वयंसेवक पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तेजी से अग्रसर हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संघ के प्रचारक बाबा साहब आप्टे ने 12 दिसंबर, 1943 को जबलपुर में गुरुदक्षिणा उत्सव पर स्वयंसेवकों से कहा- अंग्रेजों का अत्याचार असहनीय है, देश को स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संघ अपनी स्थापना के समय से ही देश की स्वतंत्रता का स्वप्न लेकर चल रहा था। भारत की सर्वांग स्वतंत्रता के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रतिज्ञाबद्ध थे इसलिए अवसर आने पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सहभागिता की, जेल गए और बलिदान भी दिया।

अंग्रेज सरकार संघ के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई थी। इसलिए उसने संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए ताकि संघरूपी आंदोलन को रोका जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले 15 दिसंबर, 1932 को एक सर्कुलर निकालकर सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं, 5 अगस्त, 1940 को ब्रिटिश सरकार ने संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया।क्योंकि सरकार को गुप्तचर रिपोर्ट में यह जानकारी मिलने लगी थी कि संघ के स्वयंसेवक पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तेजी से अग्रसर हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रहे हैं।

घूँघट की बगावत

17 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा ऑपरेशन सिंदूर: राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले को 'कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अमानवीय' बताया। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमले के प्रति भारत की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर, निर्णायक और दृढ़ संकल्प के साथ थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।

द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस वर्ष, हमें आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। कश्मीर घूमने गए निर्दोष नागरिकों की हत्या, कायरतापूर्ण और नितांत अमानवीय थी। इसका जवाब भारत ने, फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तब हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' की परीक्षा का भी अवसर था। अब यह सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं से प्रेरित होकर, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अभूतपूर्व विस्तार देखा है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की अंतरिक्ष यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। यह भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, 'गगनयान' के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। नए आत्मविश्वास से ओतप्रोत, हमारे युवा खेलों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, शतरंज में अब भारत के युवाओं का पहले से कहीं अधिक दबदबा है। हम ऐसे परिवर्तनकारी बदलावों की आशा करते हैं जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में निहित दृष्टिकोण के तहत भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए, हमें अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। हमें अपनी आदतें और अपनी विश्व-दृष्टि में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी धरती, नदियों, पहाड़ों, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के साथ अपने संबंधों में भी परिवर्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित, समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत, 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझती हूं कि अमृत काल के इस दौर में, आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में, सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे।

सड़क के कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम आदेश के व्यवहारिक मायने दिलचस्प

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सड़क के कुत्तों को पकड़ने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का निर्देश दिया है, उसके व्यवहारिक मायने दिलचस्प हैं, जबकि कतिपय नेताओं व पशु प्रेमियों ने इस सुप्रीम आदेश की सड़क छाप मुखालफत शुरू कर दी है। देखा जाए तो यह प्रेम या घृणा का मामला नहीं है, बल्कि वह सामाजिक न्यायिक पहल है जिससे सबका लोकतंत्र सुनिश्चित होता है। खासकर उन बच्चों-बुजुर्गों का जिन्हें इनसे सर्वाधिक खतरा रहता है। इसी भय से कई बार वे अकेले पार्क या पड़ोस में जाने से घबराते हैं।

दरअसल, कोर्ट ने ऐसा आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे के बढ़ने के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश दिया है। इसलिए वह आलोचना नहीं बल्कि बधाई का पात्र है। इससे मीडिया रिपोर्ट्स की गंभीरता और प्रासंगिकता भी परिपुष्ट हुई है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसका दायरा बढ़ाकर इसमें बंदरों और उन जानलेवा आवारा जानवरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

सच कहूं तो सभ्य समाज के लिए खतरा बनते जा रहे स्ट्रीट क्रिमिनल्स और स्ट्रीट बायस्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिनकी लोकल थानों व पुलिस चौकियों से सांठगांठ होती है, यदि इन जैसों के खिलाफ भी ऐसा ही सुप्रीम आदेश निर्गत हो जाए तो सभ्य समाज का भला हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लोकतंत्र उन असभ्य लोगों को आजादी का अधिकार नहीं दे सकता, जो कि समाज के अन्य वर्गों के लिए खतरा बनते जा रहे हों। संभव है कि भविष्य में न्यायालय इन विडंबना भरे सामाजिक स्थितियों पर भी गौर करेगा और बेलगाम राजनीतिक व प्रशासनिक हुक्मरानों को समाज के प्रति उसी तरह से संवेदनशील बनाएगा, जैसा कि उसके ताजा निर्णयों से महसूस किया जाता है।

बताते चलें कि अपने आदेश में कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को अगले 6-8 हफ्तों में शेल्टर रूम की शुरूआत करनी होगी, क्योंकि यहां स्थिति बेहद गंभीर है। लिहाजा, कुत्तों के काटने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन को तुरंत एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। लगे हाथ कोर्ट ने पशु प्रेमियों को यह दो टूक चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाकई, कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर शिशु और छोटे बच्चे रेबीज के शिकार नहीं होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने स्पष्ट कहा है कि इस कार्रवाई से लोगों में यह भरोसा पैदा होना चाहिए कि वे बिना डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें, बिना इस भय के कि कोई सड़क का कुत्ता उन्हें काट लेगा। इस प्रकार देखा जाए तो कोर्ट के फैसले की कुछ अन्य अहम बातें इस प्रकार हैं-

पहला, कोर्ट ने सड़क के कुत्तों को गोद लेने की दलील खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि सड़क के कुत्ते अचानक पालतू नहीं बन सकते। इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरा, मानव जीवन और सुरक्षा सबसे पहले है। इसलिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा, रोजाना पकड़े गए और शेल्टर में रखे गए कुत्तों का रेकॉर्ड बनाएं। चतुर्थ, एक सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन बनाई जाए, ताकि कुत्ता-काटने के मामलों की रिपोर्ट हो सके। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से पूछा है कि, क्या एनिमल एक्टिविस्ट और 'कथित पशु प्रेमी' उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज का शिकार हो गए।

बता दें कि कोर्ट ने गत 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मामला उठाया था, जब एक रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों, बच्चों और बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में सड़क के कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के आदेश के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया सर्कुलर जारी किया। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में बचे खाने को खुले में न फेंकें। उसे सिर्फ ढक्कन लगे कूड़ेदान में डालें, जिससे कि जानवरों के काटने की घटनाओं से बचा जा सके। सर्कुलर में इस मामले में नोटिस लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में गलियारों और लिफ्ट के अंदर कुत्तों के घूमने की घटनाओं में 'काफी' बढ़त देखी गई है। वहीं, यह सबकुछ करते हुए भी कोर्ट की भाषा विनम्र है और उसने विजिटर से भी निर्देश लागू करने में सहयोग मांगा है। जारी सर्कुलर में आगे कहा गया कि बचा हुआ सारा खाना सिर्फ कूड़ेदान में डाला जाए। किसी भी परिस्थिति में खुली जगह या बिना ढक्कन वाले बर्तनों में खाना नहीं फेंका जाना चाहिए। यह कदम जरूरी है, जिससे कि जानवरों (सड़क के कुत्तों) को खाने की गंध से आकर्षित होकर इधर-उधर घूमने से रोका जा सके। कोर्ट ने माना कि इससे काटने की घटनाओं का खतरा कम होगा और परिसर में साफ-सफाई भी बनी रहेगी। सभी आगंतुकों से इस निर्देश को लागू करने में सहयोग को कहा गया है।

बता दें कि यह सब एक स्वस्थ सामाजिक आचरण है, लेकिन जब शिक्षक व प्रशासकों ने अपनी जिम्मेदारी स्वतः न समझी और सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती गई तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उधर, कोर्ट के आदेश पर नेताओं का अलग-अलग नजरिया सामने आया है। सड़क के कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम आदेश के खिलाफ कई नेताओं, संगठनों और बॉलिवुड सितारों ने आवाज बुलंद की है। एक ओर जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर साफ कहा है कि सरकार जल्द ही एक स्ट्रीट डॉग नीति लेकर आएगी और योजनाबद्ध तरीके से कोर्ट के आदेश को लागू करेगी, क्योंकि दिल्ली के लोग इससे तंग आ चुके हैं। इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। चूंकि सड़क के कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, इसलिए हम एक नीति बनाएंगे और लोगों को राहत देंगे।

वहीं, दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला की आलोचना करते हुए कहा कि, 'हमें तो पहले से ही ऐसी ही उम्मीद थी। अब, अगर इस आदेश का पालन किया जाता है, तो दिल्ली में तीन लाख कुत्तों को पकड़कर केंद्रों में रखना होगा। दिल्ली सरकार को 1,000-2,000 शेल्टर रूम बनाने होंगे, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते आपस में लड़ेंगे। उन्हें रोकने के माकूल प्रबंध करने होंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले में तार्किक सोच अभाव है। बीजेपी सांसद गांधी ने इस मामले में पीएम से हस्तक्षेप की अपील की। जबकि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल और प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्हें हटाना क्रूरता है। तृणमूल कांग्रेस ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस आदेश पर फिर से विचार की मांग की। वहीं, जॉन अब्राहम ने कहा कि 'ये कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनसे कई लोग लगाव रखते हैं, खासकर दिल्ली के लोग...नसबंदी से इनकी आबादी पर काबू पा सकते है। उल्लेखनीय है कि डॉग लवर्स ने मंगलवार को कनॉट प्लेस पहुंचकर कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर नाराजगी जताई और इस सुप्रीम आदेश/ फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। पुनः बता दें कि गत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी सड़क के कुत्तों को 'यथाशीघ्र' स्थायी रूप से शेल्टर होम में ट्रांसफर किया जाए।

उत्तरकाशी आपदा: आखों में नींद न दिल में सुकूं, घबराहट से परेशान धराली और हर्षिल घाट के निवासी

उत्तरकाशी। पांच अगस्त को खीर गंगा के रौद्र रूप ने धराली और हर्षिल घाटी में सिर्फ घरों और संपत्तियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि लोगों के मन पर भी गहरा असर डाला है। लापता अपनों की चिंता और तबाही के खौफ से कई लोग घबराहट, बेचैनी और नींद न आने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस मानसिक पीड़ा को समझने के लिए स्टेट मेंटल हेल्थ अस्पताल सेलाकुई देहरादून के मनोचिकित्सक डॉ. रोहित गोदवाल और उनकी टीम ने धराली का दौरा किया। पहले दिन की जांच में करीब 150 लोगों में से 10 लोग गंभीर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त मिले। डॉ. रोहित ने बताया कि ये लोग ज्यादातर वे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से तबाही का मंजर देखा और जिनके परिजन अब भी लापता हैं।

डॉ. रोहित गोदवाल का कहना है कि यह पीटीएसडी (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) की स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति को बार-बार घटना याद आती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह छोटी-सी आहट से भी घबरा जाता है। दूसरे दिन के परीक्षण में भी 70 में से 10 लोग चिड़चिड़ापन और घबराहट से ग्रस्त पाए गए। सबसे अधिक प्रभावित बुजुर्ग और युवा थे। महिलाएं और बच्चों की संख्या बेहद कम है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों गंगोत्री, धराली, गंगनानी, डबरानी, भटवाड़ी और हीना में शिविर लगाए हैं। डॉ. गोदवाल ने आठ दिन तक धराली और हर्षिल अस्पताल में लोगों की काउंसलिंग की। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे खुद को अकेला न रखें, घटना के बारे में बार-बार चर्चा करने से बचें और परिवार के साथ समय बिताकर माहौल को सकारात्मक बनाएं। यदि कोई मानसिक समस्या से जूझ रहा है तो वह हेल्पलाइन नंबर 144166 पर कॉल करके 24 घंटे काउंसलिंग और मार्गदर्शन ले सकता है।

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सहसपुर देहरादून के सीएमएस डॉ. मोहन डोगरा ने बताया कि कई लोगों ने थकान और कमजोरी की शिकायत की लेकिन दवा लेने और आराम करने के बाद अब उनकी हालत सामान्य है। वहीं धराली आपदा के नोडल अधिकारी डॉ. सीपी त्रिपाठी ने कहा कि आपदा के माहौल में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को जितना हो सके खुशनुमा माहौल में रखना चाहिए।

आपदा प्रभावित महिलाओं के लिए सरकार की हेली सेवा वरदान

देहरादून। धराली आपदा प्रभावित महिलाओं के लिए सरकार की हेली सेवा वरदान साबित हुई। तीन बीमार महिलाओं को हेलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित धराली सहित सीमांत क्षेत्र के अन्य गांवों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित हेली सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं।

शुक्रवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र से गंभीर रूप से बीमार दो मरीजों एवं एक गर्भवती महिला को हेलिकॉप्टर के माध्यम से जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा गया। जसपुर गांव की 75 वर्षीय प्रतिमा देवी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद्रबाला पेट संबंधी गंभीर समस्या से जूझ रही हैं।

दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हर्षिल हेलीपैड तक लाकर हवाई सेवा से जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा। जसपुर गांव की तीन माह की गर्भवती निर्मला देवी को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। हर्षिल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भी हेलिकॉप्टर से जिला अस्पताल भेजा गया।

भारतीयों को स्वतंत्रता को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए: मोहन भागवत

भुवनेश्वर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस पर भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित किया और शांति एवं सुख की वैश्विक खोज में भारत की अद्वितीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डाला और राष्ट्र से विश्व को सद्भाव के एक नए युग की ओर ले जाने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारतीयों को स्वतंत्रता को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और त्याग करने की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ह्यहमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई .. हमें भी इसे कायम रखने, देश को आत्मनिर्भर बनाने और विवादों में उलझी दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए ह्यविश्व गुरुह्ण के रूप में उभरने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता राजेश लोया ने शुक्रवार को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शहर के महाल क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में आर-एसएस के कुछ कार्यकर्ता और प्रचारक भी मौजूद थे। लोया संगठन के नागपुर महानगर संघचालक हैं। कार्यक्रम में अपने संबोधन में लोया ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के योगदान को याद किया। भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जब भी किसी ने देश पर बुरी नजर डाली, उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लोया ने कहा कि दुनिया हैरान है कि भारत ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर दुश्मनों को हराया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हाल के वर्षों में हमारा स्वाभिमान जागृत हुआ है। उन्होंने कहा, ह्यहमह आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने ह्यस्वह्ण को जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जागृति से शुरू होती है। उन्होंने कहा, यह हमारी अपनी, हमारी स्थानीय बोली, हमारी ह्यमातृभाषाह्ण होनी चाहिए। यह हिंदी होनी चाहिए, जो व्यापक रूप से बोली जाती है। हमें विदेशी भाषाओं से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका उपयोग सामान्य संवाद तक सीमित रहना चाहिए। लोया ने कहा कि इसी तरह, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसकी का सम्मान और उसे सीखना चाहिए, क्योंकि हमें एकजुट करती है।

पिरूल से उत्पाद तैयार कर महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

अल्मोड़ा। पिरूल अब लोगों के लिए स्वरोजगार को जरिया बन रहा है। पिरूल से उत्पाद तैयार कर जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पिरूल के हटने से वनाग्नि की घटनाओं में भी कमी आई है। पीरूल वुमेन मंजू बीते पांच वर्षों से महिलाओं को पिरूल के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं।

अल्मोड़ा से करीब 60 किमी दूर द्वाराहाट के हाट गांव निवासी पीरूल वुमेन मंजू आर साह वर्ष 2012 में जीआईसी ताड़ीखेत में संविदा के तहत प्रयोगशाला सहायक के पद पर तैनात हुईं। उन्होंने साल 2019 में स्कूल की छात्राओं को पिरूल से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर अपना सफर शुरू किया। अब तक वह द्वाराहाट, रानीखेत, बग्वालीपोखर, रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका मिशन, हस्त शिल्प विभाग, एनजीओ के माध्यम से दो हजार से अधिक महिलाओं को पिरूल से टोकरी, राखियां, बैग सहित सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। प्रशिक्षण लेकर महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सालाना एक लाख से अधिक की आमदनी कर रही हैं।

लाल किले से पीएम मोदी का ऐतिहासिक 103 मिनट का भाषण

प्रधानमंत्री ने रचा नया कीर्तिमान

नई दिल्ली। आज देश अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से इस समारोह का नेतृत्व किया। स्मारक की प्राचीर से लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना संबोधन देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों, वरिष्ठ सरकारी और रक्षा अधिकारियों, और खिलाड़ियों सहित हजारों लोग शामिल हुए। सुचारू रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक नया कीर्तिमान भी रचा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट लंबा भाषण दिया, जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया सबसे लंबा संबोधन है। मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने 98 मिनट के भाषण के रिकॉर्ड को इस वर्ष तोड़ दिया। साल 2024 से पहले उनका सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण 2016 में 96 मिनट का था, जबकि उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में था जब उन्होंने 56 मिनट का भाषण दिया था। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, मोदी ने लाल किले से लगातार 12वां भाषण देकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर हैं। नेहरू ने लगातार 17 स्वतंत्रता दिवस भाषण दिए थे। मोदी ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण 2014 में दिया था, जो 65 मिनट तक चला था। 2015 में लाल किले से उनका उद्बोधन 88 मिनट तक चला था। साल 2018 में, लाल किले की प्राचीर से मोदी ने 83 मिनट की अवधि का संबोधन दिया था। इसके बाद, 2019 में, उन्होंने लगभग 92 मिनट तक भाषण दिया। 2020 में मोदी का स्वतंत्रता दिवस संबोधन 90 मिनट का था। 2021 में उनका स्वतंत्रता दिवस भाषण 88 मिनट का और 2022 में 74 मिनट का था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में 90 मिनट तक देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। वर्ष 2017 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन 56 मिनट का, 2016 में 96 मिनट का और 2015 में 88 मिनट का था। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे छोटा भाषण 65 मिनट का है, जो उन्होंने 2014 में दिया था।

मोदी से पहले, 1947 में जवाहरलाल नेहरू और 1997 में इंद्र कुमार गुजराल ने क्रमशः 72 और 71 मिनट के सबसे लंबे भाषण दिए थे। नेहरू और इंदिरा गांधी ने क्रमशः 1954 और 1966 में 14 मिनट के सबसे छोटे भाषण भी दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर कुछ सबसे छोटे भाषण दिए थे। साल 2012 और 2013 में सिंह के भाषण क्रमशः केवल 32 और 35 मिनट तक चले थे। 2002 और 2003 में वाजपेयी के भाषण और भी छोटे थे जो 25 और 30 मिनट के थे। इसके अवाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को लगातार 12 बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित कर इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस मामले में अब वह केवल जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं, जिन्होंने लगातार 17 बार यह संबोधन दिया था। इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गयी थी। उन्होंने कुल 16 बार, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को संबोधित था, जिनमें से 11 संबोधन लगातार थे। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू (1947-63) ने 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया।

धराली में आई आपदा के कारणों को अध्ययन कर लौटी टीम

देहरादून। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के कारणों को जानने के लिए गई टीम जानकारी जुटा कर लौट आई है। टीम ने स्थलीय और हवाई सर्वे के माध्यम से जानकारी जुटाई है। इसकी रिपोर्ट पर अब सबकी निगाहें हैं। पांच अगस्त को धराली में आपदा आई थी। आपदा के बाद बड़े स्तर पर राहत-बचाव और खोजबीन अभियान शुरू किया गया। शासन ने आपदा के कारण जानने के लिए टीम का गठन किया। इसमें वाडिया संस्थान, सीबीआरआई रुड़की, आईआईटी रुड़की, जीएसआई के वैज्ञानिक शामिल हैं। टीम ने 14 अगस्त को आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर अध्ययन शुरू किया था। इसमें स्थलीय और हवाई सर्वे किया। टीम ने धराली के अलावा हर्षिल में बनी झील को भी देखा। इसके अलावा हवाई सर्वे के माध्यम से खीर गंगा जिससे भारी मलबा आया था, उसके कैचमेंट एरिया को भी देखने की कोशिश की थी, लेकिन ऊंचाई क्षेत्र की तरफ काफी बादल होने के कारण खीर गंगा के पूरे कैचमेंट एरिया को देखा जाना संभव नहीं हो सका है।

ऐसे में खीर गंगा से जो मलबा धराली की तरफ आया है, वह लगभग कितनी दूरी से पहुंचा है। इसको जानने के लिए सेटेलाइट चित्रों की मदद ली जा सकती है।

यह टीम शनिवार की शाम को वापस आ गई। अब इसकी रिपोर्ट के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। इसमें आपदा के कारणों को लेकर तस्वीर सामने आ सकती है।

इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों ने अभी इससे जुड़ी बात साझा करने से इंकार किया है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कोई जानकारी दी जा सकती है।

घूँघट की बगावत

17 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

▶ 79वां स्वतंत्रता दिवस : लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का 12 वां संबोधन

आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत शुक्रवार को लड़ाकू जेट इंजन से लेकर ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन कर समृद्ध भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए कार्य बल का गठन करने दीवाली के लिए बड़े उपहार के रूप में बदलाव और सुदर्शन-चक्र नामक अत्याधुनिक रक्षा कवच की घोषणा की। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आत्मनिर्भरता पर ऐसे समय में विशेष जोर दिया, जब भारत और दुनिया बढ़ते अमेरिकी संरक्षणवाद का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा कि- आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है। तब समय की मांग है कि हमें उन संकटों का रोना रोने की जरूरत नहीं है, मैं बड़े अनुभव से कहता हूं किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है, हमें पूरी ऊर्जा, के साथ हैं अपनी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर को लंबा करते हैं तो दुनिया भी अपना लोहा मानेगी।

अपने 103 मिनट (एक घंटा 43 मिनट) के लंबे भाषण में यह भी कहा कि- मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं अगर यह रास्ता हमने चुन लिया है हर किसी ने चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। भारत की पहली सेमी कंडक्टर चिप बनाने से लेकर जेट इंजन' बनाने और परमाणु ऊर्जा के दस गुना विस्तार तक, प्रधान मंत्री नरेन्द्र

मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर अग्रसर करने जैसे लक्ष्यों वाली घोषणाएं की। उन्होंने घुसपैठ के जरिये देश की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश के प्रति आगाह किया और इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जन सांख्यिकी मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के पूर्वजों ने भारतीयों के आजादी दिलाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और यह देश के नागरिकों को कर्तव्य है कि वे ऐसी गतिविधियों को स्वीकार न करे !.

सेमी कंडक्टर, सोशल मीडिया, उर्वरक और फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और नवाचार का उनका व्यापक आहवान ऐसे समय में आया है, जब देश के अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने का फैसला किया। हालांकि, मोदी ने अपने संबोधन में टैरिफ प्रकरण का कोई हवाला नहीं दिया लेकिन आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि- सुधारों पर गठित कार्यबल - 2017 तक भारत को विकसित बनाने के लिए समयबद्ध सिफारिशें करेगी। समय की भांग है कि- हमें संकट के समय में घबराने की जरूरत नही, बल्कि अपनी क्षमताओं' और उपलब्धियों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे है उन सबका क्षेत्र होना चाहिए. दाम कम लेकिन दम ज्यादा? हमारे हर उत्पाद का दम ज्यादा हो, लेकिन दाम कम हो इस भाव को लेकर आगे बढ़ना है।

प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को दो टूक लहजे में स्पष्ट एवं कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि . आतंकवादियों और उन्हें पालने-पोसने वालों को अब हम अलग-अलग नहीं मानेंगे तथा भविष्य में किसी भी दुस्साहस की स्थिति में भारतीय सशस्त्र बल दुश्मन को मुंह-तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आपरेशन सिंदूर को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे वीर जांबाजों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है और भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उनकी इस टिप्पणी को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी के बाद प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

सीएम योगी ने फहराया विधान सभा में झंडा

स्वाधीनता त्याग और बलिदान मांगती है: सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी विधानसभा में झंडा फहराया है। इस दौरान वह परेड की सलामी ली। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता त्याग और बलिदान मांगती है। सभी वीर जवानों को नमन किया। योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया देखी। सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत दुनिया देखी। ब्रह्मोस से आतंकियों की ठिकाने ध्वस्त किए गए। ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछिए। स्वदेशी मॉडल से आतंकी ठीकाने तबाह किए गए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। स्वदेशी चीज खरीदें भारत को पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि यूपी का ओटीपी मॉडल धूम मचा रहा है। मेक इन इंडिया से देश खुशहाल होगा। 34 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया। प्राकृतिक खेती से आमदनी बढ़ेगी। कहा कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। योगी ने विपक्ष पर हमला भी बोलते हुए कहा कि पहले यूपी के सामने अर्थ का संकट था। पहले यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी। पहले बेटी व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज सुरक्षा का नया मॉडल है।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज युवा अपना लोहा मनवा रहा है। युवा अपनी प्रतिभा दिख रहा है। यूपी में निवेश का ड्रीम स्टेट बन गया है। 15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर है। यूपी आज बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर बॅकोनॉमी बनेगा। यूपी की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लखनऊ रुपए तक पहुंची है। युवाओं को बिना ब्याज के लोन मिल रहा है। जीएसटी देने वालों को बीमा कवर दिया जा रहा है। यूपी विधान भवन के समक्ष मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कलाकार प्रस्तुतियां दीं। इसके पहले योगी ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया।

पर्यावरण और विकास की साझेदारी

स्वतंत्रता के नए आयाम' का मतलब यह है कि हम अपने विकास के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए भी पर्यावरणीय बंधनों का सामना करें। इसके लिए नई सोच की आवश्यकता है जिसे सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का सिद्धान्त बताता है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। यदि हम संसाधनों का दोहन सोच-समझ कर करें, और तकनीक का इस्तेमाल इस तरह करें कि उससे प्रदूषण कम हो, ऊर्जा दाता बढ़े और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह विषय अब प्रमुख एजेंड़ा बन चुका है। 21वीं सदी में 'जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की और जैव विविधता का हास मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुके है, तब स्वतंत्रता का एक नया आयाम उभर कर सामने आया या है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। यहां की आबादी, कृषि पर निर्भरता औद्योगिक विस्तार, ऊर्जा की बढ़ती भांग और शहरीकरण की तेज गति ने विक-ास को अनिवार्य बना दिया है लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि विकास के इस रास्ते पर चलते हुए हम पर्यावरणीय संतुलन को बार-बार चोट पहुंचा रहे हैं। बनों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना, वायु और जल प्रदुषण, भूमि क्षरण और बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन ने सोचने पर मजबूर किया है कि अगर हमने दिया नहीं बदली, तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को कैसी स्वतंत्रता मिलेगी। शुद्ध हवा पानी की या केवल आर्थिक आंकड़ों की।

संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य पर्यावरण और विकास के संतुलन को वैश्विक प्राथमिकता देता है। भारत ने पेरिस समझते के तहत कार्बन उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने के लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन इन वादों को जमीन पर उतारना बाकई चुनौतीपूर्ण है और यह तभी संभव है। जब विकास की परिभाषा को न केवल आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़ा कर पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को भी शामिल किया जाए।

आखिरकार, पर्यावरण और विकास की यह साझेदारी स्वतंत्रता के नए आयाम को आकार प्रदान करती है। जो यह सिखाती है, कि - वास्तविकता स्वतंत्रता वह है जिसे हम अपनी जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ी, पीढ़ियों की संभावनाओं को क्षति न पहुंचाएं। यह केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता की भी बात है, ऐसा जीवन में जिसमे प्रकृति और प्रगति दोनों का संतुलित सह अस्तित्व हो। यदि हम इस दिशा में सही कदम उठाएं तो यकीनन स्वतंत्रता का नया आयाम न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। करेगा। यह वही स्वतंत्रता होगी जो हमें केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी सेवन बनाएगी।

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण

चौरीचौरा, गोरखपुर । क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करमहा सरदारनगर में गत गुरुवार को महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम ओपीडी में जाकर मरीजों से दवा,ईलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए । जानकारी के अनुसार पीएचसी सरदारनगर करमहा सरकारी अस्पताल का उपस्थित रजिस्टर की जांच किया। इस दौरान तीन लोग मौजूद नहीं थे। इस दौरान वह ओपीडी में मरीजों की संख्या से वह संतुष्ट दिखी। अस्पताल में भर्ती मरीजों का कहना है कि कुछ जांच बाहर कराया जाता है जिस पर उन्होंने नाराजगी जताया और शिकायत को दूर करने का आदेश दी। उन्होंने ने डाक्टरों को मरीजों को अधिक से अधिक दवाओं को अन्दर से देने के लिए निर्देशित किया।

दवाओं के स्टोर रूम का निरीक्षण किया। अस्पताल की महिला प्रसव कक्ष के शौचालय में गंदगी देखकर कडक्षी नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। अस्पताल में करीब चालीस मिनट तक रुक कर विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दी गई है। पूरे परिसर की वृहद स्तर पर साफ सफाई करवाने के लिए निर्देशित किया। राज्य महिला उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां मिली हैं,उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।डाक्टर ने आश्वस्त किया है कि अगली बार निरीक्षण के दौरान सभी कमियों को दूर कर लिया जायेगा। इस दौरान डा. ओम शिवेश मणि त्रिपाठीङ्क अरुण त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहें ॥। दमहिला आयोग की उपाध्यक्ष ने पीएचसी का किया निरीक्षण॥

मयार्दाओं का हनन : लोकतंत्र की आत्मा पर संकट

संसद की कार्यवाही अब जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का अखाड़ा बनती जा रही है। बहस की जगह शोरगुल, नारेबाजी, और बहिर्गमन ने ले ली है। जनप्रतिनिधियों की पहचान की उनके विचारों से नहीं बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन से होने लगी है। यह परिवर्तन न केवल संसदीय गरिमा को दूषित करता है बल्कि जनता के विश्वास को भी डगमगाता है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संसद और राज्य विधानसभा मात्र विधायी संस्थाएं नहीं है। बल्कि जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का मैच है। यह वह स्थान है. जहां जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं पर विचार करते हैं, समाधान सुझाते हैं और राष्ट्र की दिशा कम करते हैं परंतु विगत वर्षों में इन संस्थाओं की गरिमा पर जो आंच आई है। वह केवल चिंता जनक ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। संसद की कार्यवाही अब जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का अखाड़ा बनती जा रही है। बहस की जगह शोरगुल, नारेबाजी, और बहिर्गमन ने ले ली है। जनप्रतिनिधियों की पहचान की उनके विचारों से नहीं बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन से होने लगी है। यह परिवर्तन न केवल संसदीय गरिमा को दूषित करता है बल्कि जनता के विश्वास को भी डगमगाता है।

सत्ता पक्ष अपने विधायी एजेंडे को बिना बाधा के लागू करना चहता है जब कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग करता है। यह खींच तान अक्सर कार्यवाही को बाधित करती है जिससे संसद का बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि संकट जैसे मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं। जब संसद में इन विषयों पर गंभीर विचार विमर्श नहीं होता है तो नीतिगत सुधार भी अधर में लटक जाते हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है संसदीय शिष्टाचार का पतन । असंसदीय भाषा व्यक्तिगत आरोप और अपमान जनक व्यवहार आम हो चले हैं। कई बार सदस्यों को निलंबित करना पड़ता है जो लोकतंत्र की गरिमा के विपरीत और शर्मनाक है। यह स्थिति न केवल लोकतंत्र को कमजारे करती है, बल्कि जनता के मन में निराशा और असंतोष भी उत्पन्न करती है। ऐसा नजारा न केवल संसद का बल्कि राज्य की विधान सभाओं के सत्रों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा के मानसून सत्र में 13 अगस्त को 11 बजे से लगातार 14 अगस्त तक, की दोपहर दो बजे तक चली 24 घंटे से अधिक की कार्यवाही में भी यही नजारा देखने को मिला। इससे पहले के दो दिन भी

विरोध हंगामा और बायकाट के शिकार हुए। विधायी कार्यों के लिए जो - समय दिया जाना चाहिए वह समय एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप में व्यतीत से रहा है। जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे सदन के पटल से गायब दिख रहे हैं।

बातें तो दोनों पक्षों के बीच होती है और दावे भी होते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद खुद के वादे पूरे कर पाना विपक्ष के लिए हंगामे का एक बड़ा हथियार होता है। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार का विधान डाक्यूमेंट 2047 की चर्चा में घेरने का प्रयास किया था जिस पर सरकार ने बिंदुवार अपना पक्ष प्रस्तुत किया और विपक्ष को शांत कराने की - कोशिश की।

धूम धाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व

गोला बाजार गोरखपुर। नगर पंचायत गोला के वार्ड नंबर दो , बर्राह चौराहा स्थित सीएससी सेन्टर पर 79 वा स्वतंत्रता दिवस का पर्व क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के पत्रकारों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा शुक्रवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के प्रदेश प्रभारी बृजनाथ तिवारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया ।ध्वज को सलामी दी गई तदोपरांत राष्ट्र गान सम्पन्न हुआ। सी एस सी सेंटर के संचालक आनंद मौर्या द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा किआज के दिन हम सभी लोग जिस तिरंगे के साये में खड़े हैं। हवा में लहराता हुआ वह तिरंगा हमें सिर्फ.हमारी आजादी का नहीं, बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है, जिन्होंने अपनी सांसें इस पावन धरा के नाम कर दिया।

लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं,
यूँ ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं

ये पंक्तियां सिर्फ.कविता ही नहीं है बल्कि हमारे इतिहास की सच्चाई हैं।

जिस खुले आसमा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत शहीदों का लहू, माताओं के आंसू, और करोड़ों भारतीयों की तपस्या का परिणाम है। अतीत की कुर्बानियां हमें याद दिलाती है कि, जब भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा, तो उनके मन में कौन-सा डर रहा होगा? नहीं, डर तो कहीं नहीं था, बस एक अजीब-सी मुस्कान और दिल में देश का सपना था।, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खौल उठा होगा।, जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी, तब उनके सामने सिर्फ.युद्ध नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा था।

इतिहास किताबों में लिखे अक्षर नहीं होते, वो हमारे कंधों पर रखा भार होते हैं।अगर हम उन्हें भूल जाएं, तो हमारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। आज का दिन 15 अगस्त मात्र तिरंगा फहराने का दिन नहीं है बल्कि सभी देशवासियों के सामने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए संकल्प लेने का दिन है ।हमारे पूर्व के पीढ़ियों , देश केशहीदों द्वारा दिलाई गई आजादी को बरकरार रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने की सख्त जरूरत है।

इस अवसर पर क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के जिला उपाध्यक्ष पदमाकर मिश्रा जिला संगठन मंत्री आनन्द कुमार मौर्य, नौशाद खान, सहित हरि तिवारी,यस कुमार मौर्य, कृष्णानंद मौर्य, राजू कुमार, विशाल कुमार, मनोज कुमार , विनीत एवं ग्राम के अन्य लोगों उपस्थित रहे।

न तो इंसान सुरक्षित हैं, न ही कुत्ते

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार दुनिया में 36 प्रतिशत कुत्ते के काटने से होने वाले रैबीज से मौत के मामले भारत में होते हैं। यह संख्या 18 से 20 हजार है । रैबीज से मौतों में से 30 से 60 प्रतिशत मामलों में पीड़ित की उम्र 15 साल से कम होती है । इस पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि एक भी व्यक्ति की जान इस तरह जाए तो यह मानवता पर सवाल है और उसे बचाने के लिए सरकार और समाज को कड़े कदम उठाने चाहिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल शराब के सेवन से लगभग 2,60,000 (दो लाख साठ हजार) से ज्यादा लोगों की मौत होती है । यह आंकड़ा 2019 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि शराब सेवन से सबसे ज्यादा प्रभावित 20 से 39 वर्ष की आयु के युवक हैं। शराब के सेवन से लीवर, दिल, कैंसर व दुर्घटनाओं से जुड़ी मौतें शामिल होती हैं।

भारत में हर साल तंबाकू और गुटखा के सेवन से लगभग 13.5 लाख (1.35 मिलियन) लोगों की मृत्यु होती है। यह औसतन हर दिन 3,700 से अधिक मौतें हैं। इनमें से अधिकांश मौतें कैंसर (विशेषकर मौखिक/ओरल कैंसर), हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों, और अन्य तंबाकू जनित बीमारियों के कारण होती हैं। 90% मुंह के कैंसर के मामले भारत में तंबाकू या गुटखा सेवन से जुड़े हैं। यह आंकड़ा अभी उसी विश्व स्वास्थ्य संगठन का है ।

सवाल उठना लाजिमी है कि जो जिम्मेदार लोग कभी शराब और गुटखे पर पुरी तरह पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या अपने मोहल्ले की गली में खड़े नहीं हुए, उन्हें कुत्तों से अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई। मनुष्य ने अपने धरती पर पैदा होने के बाद सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया था। हमे पाषाण काल ल्नव पाषाण काल लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्वल्न के मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य बुर्जहोम (जम्मू कश्मीर) से प्राप्त हुआ है । आदि काल में कुत्ता इन्सान को शिकार करने में मदद करता था, फिर वह घर ०फसल की सुरक्षा भी करता था, सबसे बड़ी बात कम भोजन में भी वफादार बने रहने के उसके गुण ने आज कुत्ते को इन्सान द्वारा पाले जाने वाले सबसे विश्वस्त और सर्वाधिक संख्या का जानवर बना दिया। आखिर ऐसा क्या अचानक हुआ ?

बैलों के गले में जब घुंघरू
जीवन का राग सुनाते हैं

यह गीत कोई बहुत पुराना नहीं हैं । तब बैल घर की प्रतिष्ठा और दरवाजे पर बंधी गाय पवित्रता की प्रतीक हुआ करती थी । धीरे से ट्रेक्टर आया, जब जमीन की जोत ही छोटी हो गई और ट्रेक्टर नाम का ह्लहाथीह्व दरवाजे बांध गया तो खेती घाटे का सौदा हुई। बैल लुप्त हुए और गाय, निराश्रित , जिन लोगों ने गाय को दरवाजे से हटा कर गौशाला में ले जाने को पावन कार्य बनाया, वही वर्ग अब सड़कों से कुत्ते हटाने के तर्क गढ़ रहा है ।

ये वही वर्ग है जो सरकार की उस योजना का समर्थक है जिसमें प्रकृति के नियमो के विरुद्ध केवल बछिया पैदा करने के सीरम गाँव-गाँव बांटे जाने का समर्थन करता हैं । केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही 16 लाख से अधिक निराश्रित (आवारा) गायें मौजूद हैं। पूरे भारत में निराश्रित गायों की सटीक संख्या के लिए राष्ट्रीय पशुगणना 2025 के पूर्ण नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन पिछली गणनाओं और अलग-अलग राज्य रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 50 लाख से अधिक मानी जाती है।

जबकि हर गाँव में अनिवार्य चर्त्यी की जमीन गायों के सतह ही कौन हडप गया ? उस पर कोई बात करता नहीं । कहना गलत न होगा कि गोशालाओं की संख्या इसकी तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा है और जो हैं भी, उनमें से अधिकांश,अव्यवस्था की इस हद तक शिकार हैं कि उन्हें गायों का कब्रिस्तान कहा जाए तो अतिशियोक्ति नहीं होगी ।

क्या कभी विचार किया गया कि जलवायु परिवर्तन, खासकर बहुत तीखी गर्मी और अचानक ज्यादा या बहुत तेज बरसात का असर सीधा इन बेसहारा कुत्तों ही नहीं अन्य जानवरों पर पड़ रहा हैं और जब इंसान इतने बड़े बदलाव को समझ नहीं पा रहा है तो जाहिर है की कुत्तों को इसके साथ सामंजस्य बैठाने में समय तो लगेगा ही ।ऐसे में जब मौसम की मार में इंसान भी उन पर क्रोध दिखाता है तो उनका जानवरपन उभर आता है। इसके साथ ही दिनों दिन बढ़ते शहरीकरण के चलते बढ़ते जा रहे - शोर, ट्रैफिक, प्रदूषण, बेतरतीब पड़े कचरे से मांसाहारी खाना और फिर उस-ाका चस्का, परिसरों में रोशनी की चकाचौंध ने भी कुत्तों को असहज बना दिया है । हम-आप तो लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, शहरों में रहने वाले कुत्तों से लेकर चिड़िया तक को ऐसी सुविधा तो है नहीं!

इसी साल छः अगस्त को ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर भी विचार करना होगा जिसमें जज साहब ने कहा था कि कुत्ते दुनिया के सबसे प्यारे जानवर हैं और इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुत्तों की सुरक्षा की जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए या तो कुत्ते घर पर हों या आश्रय में। सड़कों पर कचरा खाते हुए नहीं । इंसान और कुत्ते, दोनों ही परेशान हैं। न तो इंसान सुरक्षित हैं, न ही कुत्ते। काश सर्वोच्च अदालत, इन्सान की कुत्तों के प्रति बढ़ रही नफरत के मद्देनजर उत्तराखंड हाई कोर्ट का जुलाई-2018 में दिया गया वह आदेश पढ़ती जिसमें लिखा था जानवरों को भी इंसान की ही तरह जीने का हक है। वे भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और क्रूरता के विरूद्ध इंसान जैसे ही अधिकार रखते हैं ।

धरती पर सभी जीवों का, चाहे वह इन्सान हो, का संख्या नियन्त्रण जरुरी है लेकिन उसके लिए अमानवीय तरीके, कुतर्क और अपनी जिम्मेदारी से बच कर क्रूरता का सहारा लेने का सुझाव देने वाले मानसिक रोगी ही हैं। निराश्रित कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की जिम्मेदारी उन सभी को भी लेना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असहमत हैं । यदि 50 कुत्तों की जिम्मेदारी, उनका टीकाकरण, बंध्याकरण, उसकी जानकारी उनके गले में लटके पट्टे में दर्ज करें जैसे सामान्य उपाय नागरिक समाज जिम्मेदारी से कर ले तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है ।

घूँघट की बगावत

17 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

स्वतंत्रता का अधूरा आलाप

15 अगस्त 1947 को हमने विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ दिया था। तिरंगे की फहराती लहरों में वह रोमांच था, जो सदियों की गुलामी और अत्याचार के बाद जन्मा था। हर चेहरे पर एक ही उम्मीद थी—अब अपना देश अपनी मजी से चलेगा, अब हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, अब हम अपने भविष्य के निमार्ता होंगे। लेकिन आजादी के 78 साल बाद यह सवाल कचोटता है—क्या वह सपना पूरा हुआ?

आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, विज्ञान और तकनीक में नए मुकाम हासिल हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन, डिजिटल पेमेंट, सैटेलाइट मिशन और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव हमें गर्व से भर देता है। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच छुपा है—हमारी आजादी अब भी अधूरी है। यह अधूरापन केवल गरीबी या बेरोजगारी का नहीं, बल्कि सोच, व्यवस्था और व्यवहार में गहरे बैठी असमानताओं का है।

हमारे यहां लोकतंत्र का मतलब अक्सर सिर्फ.चुनाव रह गया है। हर पाँच साल में वोट डालने को ही हम अपनी भागीदारी मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद नेता और जनता के बीच एक अदृश्य दूरी बन जाती है। जनता शिकायत करती है, सरकार सफाई देती है, और इसी बहाने असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आजादी का असली मतलब यह है कि सत्ता का केंद्र नागरिक हो, और उसकी आवाज सिर्फ.चुनावी भाषणों में नहीं, नीतियों और फैसलों में भी सुनी जाए। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बोलने की आजादी को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। लेकिन इसी आजादी का दुरुपयोग भी बढ़ा है—झूठी खबरें, नफरत फैलाने वाले संदेश, और डिजिटल विभाजन ने समाज में नई खाइयाँ बना दी हैं। आजादी तभी सार्थक है जब अभिव्यक्ति जिम्मेदारी के साथ हो, और डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल जागरूकता और प्रगति के लिए किया जाए, न कि भड़काने और बांटने के लिए। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने लंबी दूरी तय की है, लेकिन यह सफर सबके लिए एक जैसा नहीं रहा। एक ओर हम अरबपतियों की संख्या में दुनिया में आगे हैं, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग अब भी रोजगार, भोजन और इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महानगरों की ऊँची-ऊँची इमारतों की छाया में झुग्गियों की ज़िंदगी किसी को दिखाई नहीं देती। सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर नागरिक को अपनी मेहनत के दम पर जीवन सुधारने का अवसर मिले, और बुनियादी जरूरतों के लिए वह किसी के रहम पर न हो। सामाजिक स्तर पर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव आज भी हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा में बराबरी का अधिकार कागजों पर है, लेकिन हकीकत में वे आज भी असमान अवसरों और हिंसा का सामना करती हैं। यह विडंबना है कि एक ओर हम मंगल पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर लड़कियों की शिक्षा को बोझ समझने वाले विचार अब भी जिंदा हैं। शिक्षा आजादी की असली नींव है। लेकिन हमारे यहां शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में भारी असमानता है। महानगरों के निजी स्कूल और ग्रामीण इलाकों के जर्जर सरकारी स्कूल एक ही देश के हिस्से हैं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग है। बिना मजबूत और समान शिक्षा व्यवस्था के हम एक जागरूक और सक्षम नागरिक समाज नहीं बना सकते, और बिना ऐसे समाज के लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं। कोविड-19 महामारी ने हमारी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। बड़े-बड़े अस्पताल शहरों में हैं, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सपना हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह भी है कि कोई नागरिक इलाज की कमी से अपनी जान न गंवाए, और स्वास्थ्य सेवाएं केवल पैसे वालों के लिए न हों। आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है—मानसिक गुलामी। हम में से कई लोग आज भी परंपराओं, अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों की जंजीरों में बंधे हैं। बदलाव को अपनाने के बजाय हम अक्सर उसे खतरा मान लेते हैं। असली आजादी तब होगी जब हम सोचने, सवाल पूछने और नई राह अपनाने से नहीं डरेंगे। पर्यावरण संकट भी हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हवा, पानी और मिट्टी जहरीली होती जाएगी, तो नागरिक का स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भी खोखला हो जाएगा। विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बैठाना आज के भारत के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्रता केवल अधिकार लेने का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने का भी है। हम ट्रैफि क सिग्नल तोड़ते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, सफाई की अनदेखी करते हैं, और फिर भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अगर नागरिक अपने कर्तव्य निभाने में ईमानदार नहीं होंगे, तो शासन भी ईमानदार नहीं हो सकता। भारत की ताकत उसकी विविधता है। लेकिन यही विविधता हमारे लिए खतरा भी बन सकती है, अगर हम एक-दूसरे को केवल जाति, धर्म या भाषा के चश्मे से देखें। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे की पहचान का सम्मान करें और मतभेदों को दुश्मनी में न बदलने दें। अब वक्त है कि हम स्वतंत्रता को केवल ऐतिहासिक घटना की तरह न मनाएं, बल्कि इसे एक सतत जिम्मेदारी की तरह जिएं। यह जिम्मेदारी सिर्फ.सरकार की नहीं, हर नागरिक की है। हमें राजनीति में पारदर्शिता, न्यायपालिका में स्वतंत्रता, मीडिया में निष्पक्षता और समाज में समानता सुनिश्चित करनी होगी। आज के भारत को ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें हर बच्चा बिना डर और भेदभाव के स्कूल जाए, हर युवा को अपनी मेहनत के दम पर अवसर मिले, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर बुजुर्ग को सम्मान और देखभाल मिले, और हर नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। यही वह भारत होगा जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। राजनीतिक आजादी हमारी यात्रा की शुरूआत थी, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। जब तक हम असमानता, भेदभाव, गरीबी, और अज्ञानता को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्वतंत्रता का आलाप अधूरा ही रहेगा। इस अधूरेपन को पूरा करना हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है—क्योंकि आने वाले भारत की पहचान हमारे आज के फैसलों से तय होगी।

-प्रियंका सौरभ

आवारा कुत्तों की समस्या विकराल स्तर पर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या 'विकराल' स्तर पर पहुंच गई है और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निदेशों के अनुरूप इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक नीति लागू करेगी। उनकी यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने, उन्हें समर्पित आश्रय स्थलों में रखने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिए जाने के कुछ घंटों बाद आई है कि कोई भी कुत्ता वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम एक नीति बनाकर लोगों को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का दृष्टिकोण ₹नियोजित और व्यवस्थित₹ होगा ताकि जनता की सुरक्षा और अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री का यह आश्वासन उनके प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर आयोजित कई बैठकों के बाद आया है, जिसमें पिछले हफ़्ते दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस संकट से निपटने के लिए एक ₹मानवीय नीति₹ का वादा किया था। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि आगामी योजना व्यावहारिक और लागू करने योग्य होगी, जिसमें निवासियों विशेषकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों—की सुरक्षा के साथ-साथ पकड़े गए कुत्तों के लिए उचित आश्रय और देखभाल की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाएगा।

ट्रंप-मुनीर की नई जोड़ी?

ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। विगत दिनों भारतीय वायुसेना प्रमुख का वक्तव्य आया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। थलसेना प्रमुख ने भी जल्द एक युद्ध होने और आगामी युद्ध दो देशों के बीच नही अपितु कई मोर्चों पर होगा कहकर हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक की रैली में कांग्रेस नेताओं के समक्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख कर दिया जिससे पाकिस्तान का तिलमिला जाना स्वाभाविक ही है। उधर आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से प्यार हो गया है और वह दो बार वाशिंगटन यात्रा कर आया है इससे जनरल मुनीर का दिलो दिमाग खराब होना तय है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब जनरल मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिरयानी का स्वाद चखा और फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नामित किया, भारत तभी से इस मित्रता से प्रति सतर्क हो गया है। 2025 के बाद असीम मुनीर दो महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा कर आए हैं। मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला के विदाई समारोह में भाग लिया और नये कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को बधाई दी। इसमें महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अमेरिका की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें वह पाकिस्तान को ही आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र मान रहा है वह भी तब अमेरिका का सबसे बड़ा गुनाहगार पाकिस्तान में ही पाया गया था और आज भी वहां पर 126 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है, उससे मुनीर की बांछें खिलना तय है। अमेरिका में हो रही पाकिस्तानी हितों की सुरक्षा से उत्साहित पाक सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे डाली और उसके बाद अन्य पाक नेताओ के भी वैसे ही बयां आने लगे आने लग गये। इन नेताओं में पूर्व विदेशमंत्री बिलावल भुट्टो व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैं। भारत-अमेरिका संबंधों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु धमकी मिली है। रक्षा विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि मुनीर को यह ताकत अमेरिकी नीतियों के कारण ही मिल रही है। इसके पीछे एक बात यह भी हो सकती है कि अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है किंतु भारत पर अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत किसी दबाव के आगे बिना झुके अपने विकास के संकल्पों के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत-पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम हुआ किंतु भारत उनकी इस थ्योरी को बार- बार खारिज कर रहा है कि भारत -पाक के मध्य संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता के कारण हुआ। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति को बुरी लग रही है और वे पाकिस्तान से गलबहियां करते दिख रहे हैं। मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुनीर की बातो में परमाणु शक्ति संपन्न होने का अहंकार स्पष्ट दिख रहा है। उसने कहा कि जब हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। इसमे सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने के लिए उस पर हमला कर रहे हैं और ईरान को तबाह करने के लिए तैयार हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान उसकी धरती पर ही आधी दुनिया को मिटाने की बात कह रहा है।

ग्रामीण विकास को गति देतीं ग्राम पंचायतें

विजय गर्ग

भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें, तो लोक सशक्तीकरण इसकी पूर्णता है और लोक विकेंद्रीकरण की नजर से देखें, तो यह एक ग्रामीण स्वशासन की परिपाटी की पूर्ति है जो ग्रामीण विकास के लिए कहीं अधिक जरूरी है। इतना ही नहीं यह गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने को भी बल देता है। सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक है। जबकि पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्वराज को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 6.65 लाख गांव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जो देश के ग्रामीण परिदृश्य का आधार हैं। पंचायतें ग्रामीण विकास को गति दे ही रही हैं, आम आदमी की भी ताकत बन रही हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने और केंद्रित कार्यक्रमों तथा निवेशों के जरिए समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहल की गई। मसलन वर्ष 2028 तक के लिए जीवन मिशन, ब्राडबैंड सुविधा, जिसका लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इंटरनेट पहुंच उपलब्ध हो तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले एक प्रमुख सार्वजनिक 'लाजिस्टिक्स' संगठन के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, हाशिए पर पड़े समुदायों और भूमिहीन परिवारों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन फिर वर्ष 1957 में उसी की रपट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्या दूर करने का एक माध्यम माना जाता है, आज वही कई समस्याओं से जकड़ी हुई है। जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को कंधा दिया हुआ है, वही कई जंजालों से मुक्त नहीं है, चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी या फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा पुरुष वर्चस्व के के साथ जाति और ऊंच-नीच के पूर्वाग्रह ही क्यों न हों। यह समस्या पिछले तीन दशकों में घटी तो है और इसी पंचायत यह सिद्ध भी किया है कि उसका कोई विकल्प नहीं है।

पंचायत की । व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति होती है जो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत स्वशासन का बहाव भरता है और ग्रामीण बदलाव की गाढ़ी रेखा खींचता है। वर्ष 1997 का नागरिक घोषणापत्र सुशासन का ही शिखर था और 2005 में सूचना का अधिकार इसी का अगला अध्याय इतना ही नहीं वर्ष 2006 की ई-गवर्नेंस योजना भी सुशासन की रूपरेखा को ही विस्तृत नहीं करती, बल्कि इनसे पंचायत को भी ताकत मिलती है। वर्ष 1992 में सुशासन की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आई थी। वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी गई। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब वर्ष 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही यह पंचायत रूपी संस्था नए आभामंडल से युक्त हो गई। वर्ष 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।

स्वशासन के संस्थान के रूप में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। पहला संविधान में इसे सुशासन के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका सीधा मतलब स्वायत्तता और क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा यह प्रशासनिक संघीयकरण को मजबूत करता है। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्राम स्वराज को पूरा किया, मगर क्या यह बात भी पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि स्वतंत्र भारत की अति महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थानीय स्वशासन से परिपूर्ण है। पंचायतों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था जो मौजूदा समय में पचास फीसद तक है। देखा जाए तो तीन दशक से अधिक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति रूढ़िवादी सोच में अच्छा खासा बदलाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे भय, संकोच और घबराहट को दूर करने में कामयाब भी रही हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है कि पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी भी सामने आ रही है। मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल, जातिवाद और ऊंच-नीच आदि दुगुर्णों से पंचायतें मुक्त नहीं है। समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन भी शासन की एक कड़ी है। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां शोषण और सुशासन का प्रभाव हो, जिससे पंचायत में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वर्ष 2011 1 की जनगणना के अनुसार देश में चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है। पंचायत और सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जिनको पंचायत के नियम पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। आनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए कमोबेश चुनौती पैदा है। हालांकि देश की ढाई लाख से अधिक पंचायतों में काफी हद तक डिजिटल संपर्क बाकी है। साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति का कमजोर होना भी इसमें एक बाधा है।

डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है, कागजों के आदान-प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है। फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए 'रिमोट सेंसिंग', एआइ और 'माडलिंग टूल्स' का प्रयोग होने लगा है। वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बनें सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही 'ई- गवर्नेंस' कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि वह है कि राष्ट्रीय-गवर्नेंस कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभ में 31 सेवाएं शामिल की थीं। इस प्रकार की अवधारणा सुशासन की परिपाटी को भी सुसज्जित करती है। पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों की ताकत है और खास प्रकार की राजनीति से दूर है। यह ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं द्वारा स्वयं पर शासन किया जाता है। बीते तीन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सब में एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय हुई हैं। राज्य सरकारों का ऐसी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। गांवों में विकास को रफ्तार देने में इनकी भूमिका बढ़ी है।

मलोट पंजाब

पूरे देश के आवारा कुत्तों पर कार्रवाई क्यों नही?

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली/ एनसीआर के नागरिक प्रशासन और स्थानीय निकाय को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश दिये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली/ एनसीआर के नागरिक प्रशासन और स्थानीय निकाय को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश दिये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 'एनसीटी-दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करें और खासकर उन इलाकों में जहां आवारा कुत्तों का खतरा ज्यादा है। पीठ ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि आठ हफ्तों में वे आवारा कुत्तों को रखने के लिए आश्रय स्थल बनाने की जानकारी दें। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में आड़े आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पीठ ने ये भी कहा कि 'एमसीडी/एनडीएमसी और दिल्ली एनसीआर के संबंधित प्राधिकरण दैनिक आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड रखें और पकड़े जाने के बाद एक भी आवारा कुत्ता वापस छोड़ा नहीं जाना चाहिए और सभी को आश्रय स्थल में रखा जाए।' पीठ ने कहा कि अगर इस मामले में लापरवाही की गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा आवारा कुत्तों के बारे में शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए और कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वापस पुरानी जगह न छोड़ा जाए। अदालत ने कहा कि रेबीज की वैक्सीन की उपलब्धता भी चिंता का कारण है। अदालत ने वैक्सीन की उपलब्धता की भी पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नवजात, छोटे बच्चे किसी भी कीमत पर इन आवारा कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि एक हफ्ते में हेल्पलाइन स्थापित की जाए, ताकि इस पर लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं को रिपोर्ट कर सकें। न्यायालय ने कहा कि 'आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखें, अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई करें'।

जस्टिस पारदीवाला ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 'नसबंदी हो चुकी है या नहीं, सबसे पहली चीज है कि समाज आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए। एक भी आवारा कुत्ता शहर के किसी इलाके या बाहरी इलाकों में घूमते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। हमने नोटिस किया है कि अगर कोई आवारा कुत्ता एक जगह से पकड़ा जाता है और उसकी नसबंदी करके उसे उसी जगह छोड़ दिया जाता है, ये बेहद बेतुका है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। आवारा कुत्ते क्यों वापस उसी जगह छोड़े जाने चाहिए और किस लिए?' पीठ ने कहा कि हालात बेहद खराब हैं और इस मामले में तुरंत दखल दिए जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने

भी अदालत से अपील की कि वे इस मामले में सख्ती से दखल दें ताकि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सके। मेहता ने कहा कि नसबंदी से कुत्तों की सिर्फ संख्या बढ़नी रुकती है, लेकिन रेबीज का संक्रमण फैलाने की उनकी क्षमता कम नहीं होती।

सवाल यह है कि ये आदेश दिल्ली/एनसीआरके लिए ही क्यों हैं। देश में भी तो नागरिक रहते हैं। उनके लिए क्यों नही। आवारा कुत्तों का आंतक तो पूरे देश में है। देश में कुत्तों के काटने से औसतन प्रति वर्ष 29 हजार से ज्यादा व्यक्ति मरते हैं। यह तो संख्या वह है जो रिपोर्ट हो जाती है। गांव देहात के मामले से रिपोर्ट ही नही हो पाते। न वे खबरों की सुर्खियां बनते हैं। उत्तर प्रदेश का बिजनौर बहुत छोटा जिला है। यहां हाल ही में 24 जुलाई की शाम थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव झाड़पुरा भागीजोत में खेत पर काम कर रहीं 65 वर्षीय वृद्धा को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच कर मार डाला। तीन अगस्त को हीमपुर दीपा के गांव गांगू नंगला में हिंसक कुत्ते ने हमला कर दो बच्चों सहित 10 लोगों को बुरी तरह से घायल कर डाला। छह जून 2025 को अफजलगढ़ में पांच साल की बच्ची यास्मीन को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. दरअसल, बच्ची मां के साथ दूध लेने गई थी और पीछे रह जाने पर बच्ची कुत्तों के हि लग गई।

23 अक्तूबर 2023 को देश की प्रमुख चाय कंपनियों में से एक वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का निधन हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 49 साल के पराग पिछले हफ्ते अहमदाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। खुद को बचाने में वह फिसलकर गिर गए और उन्हें ब्रेन हेमरेज होने से निधन हो गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल संसद में हुए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2019 में 72 लाख 77 हजार 523 कुत्तों के हमले रिपोर्ट हुए। वहीं साल 2020 में कुल 46 लाख 33 हजार 493 कुत्तों के हमलों रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2021 में कुल 1701133 कुत्तों के काटने के मामले रिपोर्ट हुए। साल 2022, जुलाई तक भारतीय लोगों पर हुए कुत्तों के हमले की कुल संख्या स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 14 लाख 50 हजार 666 थी। इन हमलों में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये हमले आवारा और पालतू दोनों कुत्तों के हैं। इसके साथ ही इन हमलों के शिकार, बच्चे, बुजुर्ग और जवान तीनों हुए हैं।

साल 2018 में मेडिकल जर्नल लैंसेट में छापी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में हर साल 20 हजार लोग रेबीज के कारण मरते हैं, इनमें से ज्यादातर रेबीज के मामले कुत्तों द्वारा इंसानों तक पहुंचे हैं।ऐसा नहीं है कि हर कुत्ते के काटने से आपको रेबीज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज का खतरा रहता है। कुत्तों के इन हमलों के सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे, महिलाएं और जवान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि अवारा कुत्तों की परेशानी दिल्ली—एनसीआर में ही नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। देश के देहात के तो हडवार (मरे जानवर डालने के स्थान के पास) रहने वाले कुत्ते तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये महिलाएं, बीमार और बच्चों समेत अकेले आते जाते व्यक्ति को मारकर उसके मांस से अपना पेट भरते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या भारत व्यापी है। इसलिए इस मामले पर कार्रवाई भी देशव्यापी होनी चाहिए।

घूँघट की बगावत

17 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा और बलिदानों की गाथा है। इसकी असली गरिमा तभी बनी रहेगी जब इसे वही हाथ फहराएँ जो इसके लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते हैं। इसलिए गाँव-नगरों में झंडा फहराने का अधिकार शहीद सैनिकों की विरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और वर्तमान सैनिकों को मिलना चाहिए। यह परंपरा केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनेगी। राष्ट्र को बलिदान और सेवा की पहचान यही सिखाती है कि सैनिक ही असली ध्वजवाहक हैं।

सैनिक ही असली ध्वजवाहक: गाँव-नगरों में ध्वज केवल पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के हाथों में लहराए

स्वतंत्रता दिवस केवल एक तिथि या राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बलिदानों की याद दिलाने वाला दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। 15 अगस्त केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षण है। हर बार जब तिरंगा लहराता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस पवित्र ध्वज का सबसे बड़ा अधिकार आखिर कि- सके हाथों में होना चाहिए। आज यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के 79 वर्षों बाद भी हम इस सवाल का स्पष्ट और न्यायपूर्ण उत्तर खोजने में असफल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर मंचों पर अधिकतर नेता, अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि ध्वज फहराते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, लेकिन क्या यह सही है? क्या तिरंगे को फहराने का सबसे बड़ा सम्मान उन हाथों तक नहीं पहुँचना चाहिए जिनकी वजह से यह ध्वज आज स्वतंत्र आकाश में लहरा रहा है?

ध्वज का अधिकार–सिर्फ सैनिकों का

अब समय आ गया है कि पूरे देश में एक नई परंपरा स्थापित हो। राष्ट्रीय पर्वों पर–सबसे पहले शहीद सैनिकों की विरांगनाओं को झंडा फहराने का अवसर मिले। उसके बाद पूर्व सैनिकों को और फिर वर्तमान सैनिकों को।

राज्य और ज़िला स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि झंडा फहराएँ, यह स्वीकार्य है, लेकिन गाँव और नगर स्तर पर यह अधिकार केवल सैनिकों और उनके परिवारों के हाथों में होना चाहिए। यह व्यवस्था इसलिए भी उचित है क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी और के लिए प्राण नहीं देता। केवल सैनिक ही वह वीर हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। बाकी लोग अक्सर ऐसे अवसरों को अपने प्रचार और तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित कर देते हैं।

बलिदान की गरिमा

आजादी की असली क'मत वही जान सकता है जिसने सीमा पर खड़े होकर गोलियों की आवाज सुनी हो, जिसने युद्ध की भयावहता देखी हो, या जिसने अपने बेटे, पति, भाई या पिता को मातृभूमि के लिए खोया हो। बलिदान की यह गरिमा न तो राजनीतिक मंचों पर भाषणों से आती है, न ही मंच पर चमकते कैमरों से। यह गरिमा केवल सैनिक और उसका परिवार समझ सकता है। भारत के इतिहास में हर मोड़ पर यही सत्य दिखाई देता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, 1962, 1965 और 1971 के युद्ध हों, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध–हर बार सैनिकों ने अपने खून से तिरंगे की लाज रखी है। आजादी के बाद भी आतंकवाद-निरोधी अभियानों से लेकर सीमा पर लगातार होने वाली झड़पों तक, सैनिकों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, वह किसी शब्द में समेटा नहीं जा सकता।

ध्वज का प्रतीक और सैनिक की शपथ

तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसमें शांति, साहस और प्रगति का संदेश है। लेकिन इस ध्वज को सदैव स्वतंत्र रखने का संकल्प सबसे पहले सैनिकों ने लिया। जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है, तो वह केवल नौकरी नहीं करता, वह मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की शपथ लेता है। उसके लिए तिरंगा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। इसलिए जब सैनिक या पूर्व सैनिक तिरंगे को फहराता है तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि एक जीवित प्रतिज्ञा होती है। इसके मुकाबले किसी राजनेता या अधिकारी द्वारा झंडा फहराना अक्सर केवल प्र-ोटोकॉल और रस्म अदायगी भर रह जाता है।

राजनीति बनाम बलिदान

दुर्भाग्य यह है कि आज स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम अनेक जगहों पर राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बन गए हैं। मंचों पर नेताओं की लंबी-लंबी बातें होती हैं, झंडा फहराने के तुरंत बाद कैमरों के सामने तस्वीरें खिंचती हैं और लोग तालियाँ बजाकर घर लौट जाते हैं। लेकिन यदि यही झंडा किसी पूर्व सैनिक या शहीद की पत्नी के हाथों में सौंप दिया जाए तो वह क्षण केवल रस्म नहीं रहेगा। वह दृश्य श्रद्धा, बलिदान और देशभक्ति का वास्तविक संदेश बनेगा। इससे युवाओं और बच्चों को यह सीख मिलेगी कि असली नायक वे नहीं हैं जो भाषण देते हैं, बल्कि वे हैं जो खामोशी से अपना जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित कर देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

दुनिया के कई देशों में यह परंपरा है कि राष्ट्रीय पर्वों पर सैनिक या उनके परिवार ध्वज फहराते हैं। इससे सैनिकों की गरिमा और बलिदान को सर्वोच्च स्थान मिलता है। अमेरिका, रूस, इजराइल और कई यूरोपीय देशों में सैनिकों और वॉर वेटरन्स को राष्ट्रीय दिवसों पर प्राथमिकता दी जाती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहाँ सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं बल्कि आपदा राहत, शांति स्थापना और विकास कार्यों में भी योगदान देती है, वहाँ यह परंपरा और भी आवश्यक है।

युवाओं के लिए प्रेरणा

आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और आभासी दुनिया में व्यस्त है। उनके लिए देशभक्ति कई बार केवल नारे और फिल्मी गीतों तक सीमित रह जाती है। लेकिन यदि गाँव-नगरों में तिरंगा पूर्व सैनिकों और शहीदों की विरांगनाओं के हाथों में फहराया जाए तो यह दृश्य युवाओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ेगा। वे समझ पाएँगे कि राष्ट्रप्रेम केवल भाषणों और नारों से नहीं आता, बल्कि बलिदान और सेवा से आता है। यह परंपरा उन्हें सेना में जाने, अनुशासन अपनाने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देगी।

नया संकल्प

यदि हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल औपचारिक पर्व न रह जाए, तो हमें इसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संकल्प दिवस बनाना होगा। इसके लिए ध्वज को उन्हीं हाथों में देना होगा जो इसके लिए सबसे योग्य हैं। इससे न केवल सैनिकों का सम्मान होगा, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि राष्ट्रभक्ति का असली अर्थ केवल सैनिक जीवन से सीखा जा सकता है।

आज जब हम 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें याद रखना होगा कि तिरंगे का सम्मान केवल तभी सच्चा होगा जब इसे वही हाथ उठाएँ जो इसके लिए प्राणों की आहुति देने का साहस रखते हैं। सरकार और समाज यदि यह परंपरा स्थापित कर दें कि गाँव-नगरों में ध्वज केवल पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के हाथों में लहराए, तो यह न केवल बलिदान की गरिमा को स्थापित करेगा, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का नया संकल्प भी जगा देगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ

लड़की की मौत और हमारी घातक धारणाएँ

हर लापता लड़की के साथ हमारी संवेदनशीलता और सिस्टम की परीक्षा होती है। अफवाहें, ताने और लापरवाह पुलिस जाँच अपराधियों के लिए सबसे बड़ी मददगार बन जाती हैं। जब तक पुलिस हर गुमशुदगी को गंभीर अपराध मानकर तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी और समाज हर बेटी को सहानुभूति की नजर से नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियाँ दोहराई जाती रहेंगी। सरकार को दिखावटी सुरक्षा छोड़कर थानों की मजबूती पर ध्यान देना होगा। लड़की की मौत एक चेतावनी है–अब धारणाएँ बदलनी ही होंगी।

लड़की अगर घर से लापता हुई है तो वह भागी ही होगी – यह सोच केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। यही सोच एक लड़की की जान ले गई। जिस पुलिस को तुरंत उसकी तलाश करनी चाहिए थी, उसने मान लिया कि वह कहीं प्रेम प्रसंग के चलते भाग गई होगी। परिणाम यह हुआ कि अपराधियों को मौका मिल गया और एक मासूम ज़िंदगी समाप्त कर दी गई।

आज सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि बेटियों के लापता होने की शिकायत पर पुलिस की पहली प्रतिक्रिया ₹भाग गई होगी₹ और समाज की पहली प्रतिक्रिया ₹किसके साथ भागी होगी₹ होती है। दोनों ही स्थितियाँ अपराधियों के लिए ढाल बन जाती हैं। पुलिस थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले परिवारों को अक्सर यही सुनने को मिलता है कि ₹थोड़ा इंतजार कीजिए, लड़की खुद लौट आएगी।₹ यानी शुरूआत से ही मामले को हल्का समझा जाता है। जब तक पुलिस सक्रिय होती है, तब तक कई बार अपराधी अपने मंसूबे पूरे कर चुके होते हैं। यह रवैया केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जीवन के साथ खिलवाड़ है। यह मान लेना कि हर लापता लड़की प्रेम-प्रसंग में भागी है, पुलिस की सोच का सबसे खतरनाक पहलू है। इससे अपराधियों को समय मिल जाता है और पीड़ित परिवार अपने ही समाज की तानों और शक की निगाहों का शिकार बनता है। हमारे गाँव, कस्बों और शहरों में जब भी कोई लड़की लापता होती है, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लोग यह सोचने की बजाय कि वह कहीं अपराध की शिकार न हो गई हो, यह अनुमान लगाने लगते हैं कि वह किसके साथ भागी होगी। इस सोच से दोहरी चोट लगती है। एक ओर लड़की की इज्जत को बेवजह बदनाम किया जाता है और दूसरी ओर परिवार सामाजिक कलंक से टूटने लगता है।

समाज को यह समझना होगा कि हर लड़की की सुरक्षा पूरे समुदाय की ज़िम्मेदारी है। किसी की अनुपस्थिति पर अफवाह फैलाना या दोषारोपण करना न केवल अमानवीय है, बल्कि अपराध को बढ़ावा देने वाला भी है। एक लड़की की मौत केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का आईना है। पुलिस ने समय रहते खोजबीन की होती तो शायद वह आज ज़िंदा होती। समाज ने अफवाहों की बजाय संवेदनशीलता दिखाई होती तो परिवार को न्याय की लड़ाई में अकेला न रहना पड़ता। अब वह लड़की वापस नहीं आ सकती। लेकिन यह जरूरी है कि उसके हत्यारों को सख़्त सजा मिले और आने वाले समय में ऐसी त्र-ासदियाँ दोहराई न जाएँ।

आज पुलिस बल की सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी और प्राथमिकताओं की गड़बड़ी है। नेताओं की सुरक्षा में सैकड़ों जवान तैनात रहते हैं, जबकि थानों और चौकियों में फोर्स की कमी है। नतीजा यह होता है कि आम जनता की शिकायतों पर या तो देर से कार्रवाई होती है या बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी जाती है। जरूरत है कि सरकार नेताओं को दिखावटी सुरक्षा देना बंद करे और हर थाने को पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराए। बेटियों से जुड़े मामलों में फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम लागू हो और जिलों के एसपी से मुख्यमंत्री रोजाना सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लें। जब तक सरकार प्राथमिकताओं में बदलाव नहीं लाएगी, तब तक बेटियाँ असुरक्षित रहेंगी और अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट इस संकट की गम्भीरता को और भी स्पष्ट करती है। वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 90 महिलाएँ और लड़कियाँ लापता होती हैं। इनमें से कई कभी वापस नहीं लौट पातीं। वहीं हर साल हजारों मामले ऐसे दर्ज होते हैं जिनमें लापता लड़की हत्या, तस्करी या यौन शोषण का शिकार पाई जाती है। इसके बावजूद पुलिस थानों में पहला रवैया यही रहता है कि ₹भाग गई होगी।₹ यदि गुमशुदगी को शुरूआती चरण में ही गंभीर अपराध मानकर खोजबीन की जाए, तो इनमें से कई जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन हमारी सोच और व्यवस्था दोनों इस दिशा में बेहद ढीली और उदासीन हैं।

धारणा बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। जिस दिन पुलिस हर लापता लड़की को संभावित पीड़िता मानेगी, उसी दिन अपराधों पर लगाम लगेगी। जिस दिन समाज लड़की के गायब होने पर तानों और गॉसिप की बजाय सहानुभूति दिखाएगा, उसी दिन परिवारों का बोझ हल्का होगा। जिस दिन सरकार सुरक्षा को पॉलिटिकल शो-ऑफ की बजाय पब्लिक राइट मानेगी, उसी दिन व्यवस्था सुधरेगी।

आज हम नारे लगाते हैं– ₹बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।₹ लेकिन जब कोई बेटी लापता होती है, तो हमारी सोच नारे से उलट साबित होती है। ₹बेटी बचाओ₹ का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हर शिकायत पर पुलिस त्वरित और गंभीर कार्रवाई करेगी। लड़की जैसी घटनाएँ हमें झकझोरती हैं कि सिर्फ.भाषण और नारे काफी नहीं हैं। हमें अपनी सोच और व्यवस्था दोनों बदलनी होंगी। लड़की की मौत केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि हमारी पुलिस की जाँच शैली बदलनी होगी, समाज को अपने पूर्वाग्रह छोड़ने होंगे और सरकार को अपनी प्राथमिकताएँ सुधारनी होंगी। वह लड़की लौट नहीं सकती, लेकिन अगर उसके हत्यारों को सजा मिले और उसकी मौत से सबक लेकर सिस्टम बदले, तो उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर यह तय करें कि हर बेटी सुरक्षित है और उसकी गुमशुदगी को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

डॉ. प्रियंका सौरभ

व्यंग्य : कुत्तों को दिल्ली से बेदखल करो..!

एक अनुमान के मुताबिक भारत में छह करोड़ आवारा कुत्ते है पर हमारे पड़ोस वाले हरिशंकर परसाई कह रहे थे कि इनकी ब्रीड संख्या 99 है और कुल नश्ली और गैर नश्ली मिलाकर लगभग दो सौ कुछ ज्यादा है जो विपक्ष की सीट पर बैठते है। अब कोई कह रहा था कि इनका भी एसआई आर किया जायेगा और इन्हे जल्द ही गेट आउट किया जायेगा। अब एक अन्य आंकड़े के अनुसार तीन करोड़ पालतू कुत्ते है जबकि हमारे बगल वाले पीडीए वाले चचा कह रहे कि नहीं इनकी संख्या हमसे कुछ कम है। मैंने पूछा हमसे का मतलब बोले अरे गलती से मुँह से निकल गया। मैंने पूछा गलती कैसे तो बोले अब क्या पूजा पाल कि तरह पार्टी से निकलवा दोगे क्या ! कुत्तों पर तगड़ा संकट है। अरबी नश्ल के श्वानो की शामत आ गई है। बाबा चिमटा लेकर सदन से भगा रहे। आदमी कह रहा है कुत्ते हिंसक हो गए है बैरिकेटिंग तक कूद फांद जा रहे। मगर कुत्ते कह रहे है हम तो बइलट पेपर से चुनाव करवायेंगे ताकि आसानी से खुद को हारता देखकर उसमें सू कर के भांग जाए। इंसान की संगत से कुछ का मिजाज हिंसक हो गया है। वरना कुत्ते ऐसे नहीं थे । कुत्तों के निष्कासन पर सभा बैठी ! ये श्वानो की सभा संसद थी। न कोई हाथापाई न कोई गाली गलौज।देश की आला अदालत का फरमान है कुतो को दिल्ली से बेदखल करो। कुत्ते वोटर को काटने लगे है। कुत्तों ने इसे गलत बताया है। कहने लगे हमारे मलिक पप्पू के पापा और उनकी दादी ने कितनो को काटा है ,उनका भी जिक्र हो। इस साल की तपती मई में हमने किसी को काटा नहीं हम तो बैंकोग थे ।

उधर सभा में असली कुत्तों पर अत्याचार के विडिओ चल रहे वीसीआर पर, ग्रेटर नोएडा में एक आदमी ने कुत्ते को इ रिक्शा से बांध कर 500 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के सिसोली में एक व्यक्ति ने कुत्ते को पूंछ से पकड़ कर घुमाया और जमीन पर पटक कर श्वान की जान ले ली।

मेरठ में गौरी त्यागी ने नीट पास किया और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक स्ट्रीट डॉग घायल हुआ। गौरी ने जख्मी जानवर का इलाज करवाया और रोज दवा देने लगी। लेकिन कुत्ता चल बसा। गौरी इतनी विचलित हुई कि खुदकुशी कर ली।

राजस्थान के जोधपुर में 2022 की बात है। मेडिकल साइंस पढ़े एक डॉक्टर ने गली के कुत्ते को गाड़ी के बांधकर किलोमीटर तक घसीटा।झुंझुनू में इसी हफ्ते एक आदमी ने बंदूक से 25 कुतो को मौत की नींद सुला दिया।उज्जैन धर्म नगरी है। पांच कुत्तों को तेजाब से जला दिया गया।कुत्ते पूछ रहे है फिर हम पर इल्जाम क्यों ? कुत्ते पांच हजार साल से इंसान के साथ है/लेकिन हे धर्मराज तुमने तो अपने कुत्ते के लिए स्वर्ग का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। पर उसी भारत में जब धर्म की बयार प्रबल हुई तो इंसान और श्वान के रिश्ते दरकने लगे है। भारत विरोधाभास की धरती है। केम्ब्रिज अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन कहती है भारत में जो कुछ आप देख रहे है वो सच है। मगर इसके उल्ट भी उतना ही सच है।

मेरठ में गौरी त्यागी ने नीट पास किया और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक स्ट्रीट डॉग घायल हुआ। गौरी ने जख्मी जानवर का इलाज करवाया और रोज दवा देने लगी। लेकिन कुत्ता चल बसा। गौरी इतनी विचलित हुई कि खुदकुशी कर ली। उसी भारत में पत्रकार गौरी लंकेश को कुत्ते की मौत मार डाला गया।दिल्ली में 80 वर्ष की प्रतिमा देवी कोई दो सो कुत्तों को रोज रोटी खिलाती है। उसे डॉग मदर कहते है।वो न आये तो कुत्ते रोटी नहीं खाते। एक भारत ये भी है। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला है/ कोई दिसंबर की सर्द रात में एक दूध मुंही को वीराने में फेंक गया।सुबह झुरमुट में से एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी।लोग उधर पहुंचे तो देख कर स्तबध रह गए। देखा एक मादा डॉग अपने पांच बच्चों के साथ आगोश में समेटे एक नवजात कन्या को लिए बैठी है।फीमेल डॉग ने उस नवजात की तब तक पहरेदारी की जब तक कि कोई इंसान लेने न आ जाये।जब उस बालिका को लोग ले जाने लगे तो फीमेल डॉग ने ये जरूर कहा होगा ' बिटिया हम तो जानवर है ,आगे इंसानो की बस्ती है ,दामन बचा कर रखना।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

कृषि सुधार के 78 वर्ष: स्वतंत्रता के बाद से कृषि में भारत की उल्लेखनीय यात्रा

विजय गर्ग

स्वतंत्रता के बाद से कृषि में भारत की यात्रा एक उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी रही है, जिसे सुधारों और नीतियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है जिसने देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया है। भोजन की कमी से जूझ रहे देश से लेकर एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक और निर्यातक बनने तक, भारत के कृषि सुधार इसकी विकास कहानी की आधारशिला रहे हैं। फाउंडेशन वर्ष (1947-1960): स्क्रैच से भूमि सुधार और भवन स्वतंत्रता के समय, भारत के कृषि क्षेत्र की विशेषता कम उत्पादकता, एक शोषक भूमि कार्यकाल प्रणाली और मानसून की बारिश पर भारी निर्भरता थी। सरकार का प्रारंभिक ध्यान इन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करने पर था। बिचौलियों का उन्मूलन: पहला बड़ा कदम जमींदारी प्रणाली को समाप्त करना था, जिसने गैर-खेती करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बनाया था। इस सुधार का उद्देश्य टिलर को भूमि का मालिक बनाना था, जिससे उन्हें अपने खेतों में निवेश करने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

भूमि छत और पुनर्वितरण: भूमि जोत के आकार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाए गए थे जो एक व्यक्ति स्वयं कर सकता था। अधिशेष भूमि को तब भूमिहीन किसानों को पुनर्वितरित किया गया था। जबकि इन सुधारों का कार्यान्वयन राज्यों में भिन्न था, उन्होंने अधिक न्यायसंगत कृषि संरचना के लिए आधारशिला रखी।

प्रारंभिक योजना: कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में उच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश, जैसे भाखड़ा बांध, और कृषि अनुसंधान और विकास के लिए संस्थानों की स्थापना थी। हरित क्रांति (1960ः-1970ः): आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग 1960 के दशक में भोजन की गंभीर कमी का दौर था, जिससे "शिप-टू-माउथ" अस्तित्व बन गया, जहां भारत खाद्य सहायता पर बहुत अधिक निर्भर था। इस संकट ने हरित क्रांति के शुभारंभ में समापन करते हुए नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव को प्रेरित किया।

उच्च उपज वाली किस्में : हरित क्रांति गेहूं और चावल के बीज की नई, उच्च उपज वाली किस्मों की शुरूआत से प्रेरित थी। इन्हें एक "पैकेज दृष्टिकोण" के साथ जोड़ा गया था जिसमें आधुनिक खेती तकनीक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक शामिल थे।

सिंचाई और मशीनीकरण: सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक सिंचाई सुविधाओं, जैसे नलकूपों और यंत्रीकृत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया।

संस्थागत सहायता: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और कृषि मूल्य आयोग (अब सीएसीपी) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना किसानों के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने, बफर स्टॉक बनाए रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। हरित क्रांति एक

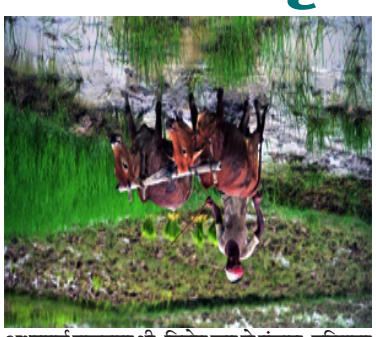

अभूतपूर्व सफलता थी, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। इसने भारत को खाद्य-घाटे से खाद्य-अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया, जिससे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। हालांकि, इसने पानी की कमी और मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्षेत्रीय विषमताओं और पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया। हरित क्रांति के बाद का युग (1980ः-2000ः): विविधीकरण और उदारीकरण हरित क्रांति की सफलता के बाद, इन लाभों को अन्य फसलों और क्षेत्रों में विस्तारित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया।

खाद्यान्न से परे "क्रांतियाँ": इस अवधि में अन्य लक्षित कार्यक्रमों, जैसे ऑपरेशन फ्लड (डेयरी, श्वेत क्रांति), पीली क्रांति (तिलहन), और नीली क्रांति (मत्स्य पालन) का शुभारंभ देखा गया, जिसने विविधता लाने में मदद की भारत का कृषि उत्पादन।

बाजार सुधार: 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण कृषि नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। निर्यात बाधाओं को हटा दिया गया था, और किसानों को वैश्विक बाजार के लिए नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने नए अवसर खोले लेकिन किसानों को वैश्विक मूल्य अस्थिरता से भी अवगत कराया।

प्रौद्योगिकी का उदय: जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार और बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों और कृषि आदानों के उपयोग के साथ प्रौद्योगिकी पर जोर जारी रहा। हाल के सुधार (2010-वर्तमान): स्थिरता और किसान कल्याण की ओर हाल के दशकों में, कृषि सुधारों का ध्यान किसानों के लिए इस क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लचीला और लाभदायक बनाने पर रहा है।

किसान कल्याण योजनाएं: सरकार ने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई प्रदान करने के लिए), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा), और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (आय समर्थन)।

जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य: परमपरागट कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी मिट्टी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक धक्का दिया गया है।

डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचा: प्रभावी योजना और नीति-निर्माण के लिए एक फेडरेटेड डेटाबेस बनाने के लिए "एग्रीस्टैक" जैसी पहल शुरू की गई है। सरकार ने गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। द जर्नी सो फार: की आउटकम पिछले 78 वर्षों में, भारत के कृषि सुधारों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है:

खाद्य घाटे से लेकर खाद्य अधिशेष तक: भारत अब दूध, दालें, मसाले, फल और सब्जियों सहित कृषि वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

बढ़ी हुई उत्पादकता: फसल उत्पादन और उत्पादकता में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

आर्थिक योगदान: कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आजीविका प्रदान करता है और देश के निर्यात में योगदान देता है। जबकि जलवायु परिवर्तन, छोटे लैंडहोल्डिंग, और बेहतर बाजार संबंधों की आवश्यकता जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं, स्वतंत्रता के बाद से भारत के कृषि सुधारों की यात्रा एक आत्मनिर्भर और खाद्य-सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।

घूँघट की बगावत

17 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

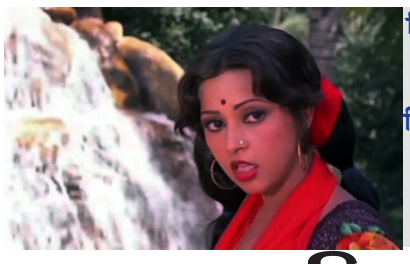

हिंदी फिल्म जगत की दर्द भरी कहानी रही है जहोएक चमकता सितारा अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। पर कुछ कहानियों सिपी गुम नहीं होती वह अपने पीछे एक अनसुलझे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका जवाब 'आज तक नहीं मिला यहां हम एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जो गरीबी से उठकर बड़े पर्दे तक पहुंची लेकिन मात्र 33 साल की उम्र में जिसकी लाश उसके अपार्टमेंट में पाई गई, इनकी मौत आज भी एक रहस्य बन कर रह गई।

सहायक भूमिकाओं में बंधी रहीं मधु मालिनी

शिव काका अपने साहब से कर दो हम उनसे नहीं बोलेंगे। हम उनसे नाराज हैं।' हो हो नहीं बोलेंगे आज हमारे छोटे भैया का जन्म दिन है और फिर भी आज पापा देर से आए।

'मधु मालिनी जिसका असली नाम रुखसाना था।उनका जन्म 1950 के 12 दशक के आखिरी सालों में मुंबई के माहीम इलाके में हुआ था । उनका परिवार बेहद गरीब था लेकिन इस गरीबी ने उनके सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। फिल्म जगत में कदम रखने से पहले ही अपनी जिंदगी में एक ऐसी मंजिल तय कर ली थी जहां भले ही सुपर स्टारडम न मिला हो लेकिन उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली थी। उनके करियर की शुरूआत छोटे-छोटे किरदारों से हुई जहां उन्हें अक्सर एक जैसे रोल मिले। 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा और 1977 की ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाओं ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई लेकिन उनके करियर का असली मोड़ 1978 में मुकद्दर का सिकंदर' से आया, इस फिल्म में उन्होंने अभिताभ बच्चन की बहन की भूमिका निभाई। उनके सहज अभिनय न दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया और उन्हें एक भरोसेमंद सहायक अभिनेत्री के तौर पर जाना जाने लगा। यहां से उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने

लावारिस (1981), एक दूजे के लिए (1981) खुद्दार (1982) और रजिया सुल्तान (1983) जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया।इसके साथ पर्दे पर वह हमेशा बड़े कलाकारों के साथ सहायक भूमिकाओं में नजर आई। उनका किरदार कहानी को गहराई देता था। भले ही वह केन्द्रीय भूमिका में नहीं रहीं। मधु मालिनी की सबसे खास बात उनकी शक्ल थी। उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री हेमा मालिनी से इतना मिलता जुलता था कि लोग उन्हें हेमा मालिनी की हमशक्ल कहने लगे। इंडस्ट्री के अंदरुनी लोग और दर्शक दोनों ने उनकी शक्ल में समानता को महसूस किया और यही समानता उनके स्क्रीन नाम का आधार बनी। उनका असली नाम रुखसाना था लेकिन इसी समानता की वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर मधु मालिनी रख लिया। ये नाम उनसे ऐसे जुड़ गया कि उनकी असली पहचान कहीं पीछे छूट गई एक अभिनेत्री जो

कभी छोटे मोटे रोल करती थी अब बड़े सितारों के साथ- काम कर रही थी। उनके अभिनय की रेंज भी कमाल की थी। 1983 में आई फिल्म अवतार में उन्होंने एक खराब बहू का नकारात्मक किरदार निभाया। ये रोल काफी चर्चित हुआ हुआ और इसने एक बहुमुखी अभिनेत्री के तौर पर उनकी जगह को और मजबूत कर दिया लेकिन अफसोस की बात यह कि एक के बाद एक तारीफ पाने के बावजूद भी वह हिन्दी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका नहीं कर पाई। वह हमेशा एक सहायक भूमिकाओं में बंधी रह गई। बॉलीवुड में हैं जो नहीं बिना वह उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा में मिला। मधु मालिनी ने पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी कला का विस्तार किया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी अपनी पहचान बनाई। 70 और 80 के दशक में वह लगातार काम करती रहीं हालांकि वह कभी सुपर स्टार नहीं बन पाई पर उनकी पर्दे पर मौजूदगी हमेशा बनी रही। 1983 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म आम्बी में मुख्य अभिनेत्री का रोल मिला ये उनके लिए एक बड़ा मौका था क्योंकि थे उनकी बतौर हिरोइन, आखिरी फिल्म साबित हुई। मधु मालिनी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्यों कि उनका जीवन एक रहस्य बन गया। आम्बी की रिलीज के बाद वह अचानक हिंदी फिल्म जगत से गायब हो गईं, हालांकि इसके बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं - इंतकाम की आग. वो मिली थी, जिंदगानी, कांच की दीवार, सलमा, प्यार कभी झुकता नहीं, और जख्मी शेर लेकिन ये वह फिल्में थीं जिनमें उनका किरदार बहुत छोटा था। इन सभी फिल्मों की शूटिंग उन्होंने आम्बी के रिलीज होने के पहले ही कर ली थी। कहने का मतलब यह कि 1983 के बाद मधु मालिनी कभी मुंबई वापस नहीं आईं। एक ऐसी अभिनेत्री जो बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही थीं। वह अचानक कहां चली गई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कोई सवाल नहीं पूंछा सिवाय एक पत्रिका के। सिने ब्लिट्ज में प्रकाशित एक लेख में इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की जिसमें लिखा था कि मधु शालिनी ने अपने गाता-पिता को बिना बताए एक लड़के से भाग कर शादी कर ली। उनके परिवार वाले उनके इस फैसले से नाराज हुए कि उन्होंने मधु शालिनी के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए।

1947 का वह दिन जब देश के बंटवारे के दौरान नफरत और हिंसा की वजह से अनेक लोग बेघर हो गए जिनकी स्मृति में 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। इस विभाजन में कइयों के अपने दिल टूटे, घर टूटे, अपने छूटे और सबकी निगाहों में छा गया विभाजन के दंश का खौफनाक मंजर, जो आज भी दिल दहलाने का दमखम रखता है।

विभाजन की भयावहता को प्रदर्शित करत फिल्में

उस दौर की अनेकानेक दुश्वारियों को उकेरतीं संवेदनशील मुद्दों को स्पर्श करतीं बॉलीवुड ने अनेक फिल्में समाज को दीं जिनका उल्लेख यहां पर किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चंद्र प्रकाश द्विवेदी में' प्रख्यात उपन्यासकार अमृता प्रीतम के चर्चित उपन्यास पर आधारित पिंजर का निर्माण किया जिसमें विभाजन के दौरान महिलाओं की पीड़ा को उकेरा गया। वर्ष 2003 में प्रदर्शित इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के द्वारा निभाए गए पूरो के किरदार को दर्शकों में काफी सराहा और प्यार भी दिया। 'पूरो एक हिंदू लड़की है जिसका अपहरण एक मुस्लिम युवक कर लेता हैं। - यह फिल्म सामाजिक बंधनों, नफरत और मानवता के बीच की जटिलताओं' को उजागर करती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने के लिए विवश कर देती है। इसी वर्ष 2003 में सबीहा समर की फिल्म- खामोश पानी पाकिस्तान में बसे एक गांव की कहानी है जहां विभाजन की यादें एक महिला और उसके बेटे की कहानी कहती है। किरण खेर की अभिनय क्षमता वाली यह फिल्म एक पंजाबी गांव में रहने वाली विधवा मां और उसके बेटे की दास्तां कहती है।

अमित शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर विभाजन के दौरान प्रेम और बलिदान की कहानी को पर्दे पर पेश करती है। साल 2001 में प्रदर्शित इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में है। यह फिल्म एक सिख ट्रक ड्राइवर तारासिंह और मुस्लिम लड़की सकीना प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में विभाजन की हिंसा और नफरत के बीच तारा अपनी पत्नी और बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है।

1947: अर्थ एक इंडो कैनेडियन पीरियड रोयोस ड्रामा फिल्म है जो 1999 में दीपा मेहता के निर्देशन में बनी है। यह बाप्सी सिधवा के उपन्यास के किंग इंडिया पर आधारित है। जो 1947 के भारत विभाजन के समय की कहानी है। कहानी 1941 में लाहौर में भारत विभाजन के समय की है। पोलियो ग्रस्त लेनी एक धनी पारसी परिवार की लड़की रहती है जो अपनी कहानी सुनाती है। उसके माता- पिता, बेटी और रुस्तम और आया शांता उसकी रक्षा करते हैं। शांता के प्रेमी दिल और हसन उसकी देख भाल करते हैं। इसी प्रकार से विभाजन के दंश का असर खुशवंत सिंह के उपन्यास पर आधारित पामेला रुक्स की फिल्म ट्रेन टु पाकिस्तान साल 1988 में आई फिल्म भी एक पंजाबी गांव की कहानी प्रदर्शित करती है। जहां सिख और मुस्लिय समुदाय शांति से रहते है लेकिन विभाजन की हिंसा गांव को भी अपनी चपेट में ले लेती है।

क्या पुलिस राजनीति का हिस्सा बन गई

प्रदेश में पुलिस का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं है। यदि ऐसा न होक तो आज यह स्थिति नहीं आती। पुलिस खुद उस कानून के आगे नतमस्तक नहीं है जिसकी शपथ लेकर वह नौकरी में आई है। यही कारण है कि उसे कार्रवाई करने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ता है कि उसके आका क्या चाहते है।

फतेहपुर में मजार मकबरे को लेकर जिस प्रकार से हिंदू संगठनों ने दावा किया तारीख घोषित करके घटना को अंजाम दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यह स्थिति चिंताजनक है। हिंदू संगठन का नाम रख कर दंगाइयों, हुड़दंगियों की यह सेवा देश के अंदर जिस प्रकार से आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रही है। वह लोगों की नजर में ढका छिपा नहीं रह गया है। एक तरफ मस्जिदों मजारों मकबरों में मंदिरों की खोज की जा रही है। अदालतों मे मुकदमे दायर हो रहे हैं। आस्था बताई जा रही है लेकिन क्या आस्था सिर्फ कि- सी एक संगठन राजनीतिक दल की होगी या औरों की भी कोई आस्था हो सकती है। इस घटना को लेकर जहां विधान सभा में हंगामा रहा है वहीं विपक्ष यह आरोप भी लगाता रहा है कि जिसने इस घटना को अंजाम देने की घोषणा किया था वह या तो सत्तारूढ दाल का जिलाध्यक्ष है लेकिन उसका नाम ही उस प्राथमिकी में नहीं है जिसके बारे में यह सरकार कह रही है कि - इस मामले में दस नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा घटना के बाद शाम को ही दर्ज हो गया। सरकार इस घटना के बारे में किसी प्रकार की संलिप्तता के बारे में पल्ला झाड़ रही है।

जहां तक मकबरे को तोड़े जाने उस पर भगवा लहराने और हनुमान चालीसा पढ़े जाने और उद्दंड लोगों द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने का प्रश्न है। क्या सरकार इसे अपने कानून व्यवस्था के फेल होने को नहीं मानेगी। जो सरकार देश में सबसे अच्छा कानून व्यवस्था होने का दावा करते नहीं थकती। यह सवाल किसी भवन या मकबरे को तोड़ने से लेकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का है लेकिन चूंकि ऐसे संगठन खुद को हिंदू संगठन घोषित करते है इसलिए इनके खिलाफ उस प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है जो दूसरों के खिलाफ पिछले आठ वर्षों से बुलडोजर से घर ढहाने या हाफ एन काउंटर कर या फुल एन- काउंटर करके मुद्दे को ही समाप्त करने का काम करती आई है। यद्यपि किसी भी दशा में न तो हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर का समर्थन किया जा सकता है और नही बुलडोजर की कार्रवाई का लेकिन ऐसे कृत्यों को कहां से समर्थन मिला रहा है अब यह किसी से दिया नहीं है। यह तो अब खुला खेल फरुर्खाबादी हो गया है। मामला -चारे ग्राहम स्टेंस की हत्या का हो या बाबरी मस्जिद -ध्वंस का, अयोध्या में मजारों के ध्वंस का हो या मस्जिदों के ध्वंस का गोवंश गौमांस के नाम पर माब लिंचिंग का आखिर कौन से लोग इनमें शामिल रहे और उन्हें कौन सा दण्ड मिला है।

क्या इसके लिए सरकार कोई फास्ट ट्रेक आदालत बनायेगी जिसमें छः माह में परिणाम आ सकें। ऐसे मामलों में लोगों को सजा क्यों नहीं मिल पाती ? अयोध्या विवाद को यदि देश में एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्थिति स्वतः स्पष्ट है कि किस प्रकार लोग क्लीन चिट पा जाते हैं और जांच एजेंसियां 'अपील तक में नहीं जाती है। तकनीकी उलझाव में उलझाकर मुकदमे को यहां तक खींचा जाता है कि सब पाक साफ निकले। यही हुआ है।'

प्रदेश सरकार चाहे जितना पल्ला झाड़ ले कि किसी भी प्रकार का सिस्टम (तंत्र) इन्वॉल्व नहीं है लेकिन मौके की स्थितियां स्वयं गवाही देती है कि- करणी सेना में क्या किया? फतेहपुर, मकबरे में क्या हुआ। इन मामलों में प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी। क्या वह सरकार में नंबर बढ़वाने में लगी थी कि वह क्यों काम करे और सरकार की नजर में नुकसान उठाए। वही क्या एक राजनीति का हिस्सा बन गई है।

हिन्दी फिल्म जगत की अभिनेत्री नाजिया एक ऐसी कलाकार रहीं हैं जो आज से लगभग 50 साल पहले सिनेमा जगत से रुखसत होकर कहीं दूर चली गई थी लेकिन उनके चले जाने के बाद फिल्मी गलियारों में नाजिया के नाम को लेकर जो गलत फहमियां फैली उन्हें उन्हें सच साबित होने में 40 साल लग गए। 21 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका है। इस बात को लगभग सभी लोगो ने मान लिया था। लेकिन 2020 में उनके जिंदा होने की खबर लोगों के सामने आई। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि नाजिमा सचमुच मर चुकी हैं तो शायद ही कोई यकीन कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है कि 11 अगस्त 2025 के दिन हिन्दी सिनेमा की लोक प्रिय अभिनेत्री नाजिमा गुजर गईं।

यह है बॉलीवुड की सिस्टर नाजिमा उर्फ मेहरुन्निसा

कोई माने या ना आने, जो कल तक थे अंजाने वो जान से प्यारे हो गए- ये राखी बेधन है ऐसा जैसे गीतों की धुन पर अभिनय करने वाली नाजिमा का वास्तविक नाम मेहरूनिस था। 25 मार्च 1948 को नासिक में जन्मी इस बच्ची ने अल्पायु में फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था।

'हां भैया! मैं भी तुम्हारे साथ चल - चलूंगी मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती हैं। जानते हो भइया एक दिन तो भाभी ने कुछ मी नही खाया।'

जब देखो रूपए रुपए रुपए हर महीने एक रुपया हेरी नाक पर धरती हे। और पांच रूपए डिपाजिट के अलग ले रखे हैं। - जैसे संवाद भी कभी कभी कानों में गूंज जाते हैं।

नाजिया के परिवार का फिल्मों से पुराना नाता था। उनकी दादी शरीफा बार्ड और खाला हुस्न बानो दोनों ही फिल्म जगत की जानीमानी अभिनेत्रियां थी। हुस्न बानो की शादी निर्देशक हस्वी ईरानी से हुई थी और मेहरूनिस उनके भाई नादिर शाह की बेटी थीं।

नाजिमा को बचपन में बेबी बांद के नाम से जाना जाता था और वह जल्द ही विगत रॉय जैसे महान निर्देशकों की नजरों से आ गई। देवदास में उन्होंने - छोटी पारो की सहपाठी (क्लासमेट) का किरदार निभाया था और दो बीघा जमीन में वह दो बहनों में से बड़ी बहन के किरदार में नजर आई। इसके अलावा विमल राय की एक और फिल्म गेराज बहु में उन्होंने लीड एक्ट्रेस अभि भट्टाचार्या की बहन की भूमिका निभाई थी ।' खामोश है लब वो मंजिल है' जब ईश्क कहीं हो जाता है।)

राजकपूर की फिल्म - अब दिल्ली दूर नहीं' (1957) में भी उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। जैसे जैसे जब वह बड़ो हुई उनका अभिनय और भी निखरता गया लेकिन साथ ही उनका दर्द भी बढ़ता गया। वह एक सहायक अभिनेत्री बन कर रह गई जिन्हें प्यार से बॉलीवुड की बहन या रेसिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा' 'मदद कीजिए राजदा ए मदीना ।

नाजिमा ने फिल्मों में इतनी ज्यादा बहनों की भूमिका निभाई कि- निमार्ता निर्देशक उसके अलावा कोई और भूमिका उन्हें दे ही नहीं पाते थे। राजेश खन्ना के साथ औरत और डोली, मनोज कुमार के साथ बेईमान में राजेन्द्र कुमार के साथ आरजू में वह हमेशा बहन की भूमिका में ही नाजर आईं हालांकि बेईमान में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें 1972 में फिल्म फेयर सर्व श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया था पर उनकी टीस कम नहीं हुई।

एक साक्षात्कार में उन्होंने उस दर्द को जाहिर करते हुए कहा था- मैं नहीं जानती मेरा भविष्य क्या है। मैं लीड हिरोइन का किरदार निभा सकती हूं लेकिन फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए मैं ये किरदार भी निभाती रहूंगी - वरना लोग मुझे भूल जाएंगे। ये मोहब्बत का असर है दिल की मस्ती है। नाजिमा सिर्फ बहन की भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं थी। फिल्म अभिनेत्री में वह हेमा मालिनी की चुलबुली सहेली बनकर, मनचली में लीना चंदावरकर की सहेली बन कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कुछ सीन्स आज भी याद किए जाते हैं। इसके बावजूद उनके मन में एक टीस लगातार बनी रही वह लीड हिरोइन बनना चाहती थीं । उन्होंने 1964 में फिल्म विद्यापति में भारत भूषण के साथ, 1967 में वही लड़की में हीरोइन का किरदार भी निभाया। लेकिन इन फिल्मों को ज्यादा सफलता नहीं थी। उनके कैरियर ग्राफ में ऊंचाइयां थीं, पर कहीं न कहीं वह अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थीं। उनके अभिनय को सराहा जा रहा था लेकिन एक एक्ट्रेस के लिए फिल्म में मेन लीड की जो अहमियत होती है। वह शायद उन्हें कभी महसूस नहीं हुई लेकिन फिर 1957 में अचानक से नाजिया गायब हो गई। उनका कॅरियर पर्दे पर चमक रहा था फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके अचानक गायब होने की वजह किसी को समझ नहीं आई। यहीं से शुरू हुई अफवाह की कहानी, उनके गायब होने की बात को लोगों ने - कैंसर से जोड़ लिया कि नाजिया को कैंसर होगा। 2020 तक इस अफवाह ने राज किया।

यादगार लम्हात

गत दिनों रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से पुराने दोस्त की तरह बात जिससे उनका यह लम्हा जीवन भर याद रखने वाला बन गया। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नम्मा मेट्रो येलो लाइन और अनेक रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन जैसे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच बच्चों के साथ बैठे हंसी-मजाक किये और उनकी कहानियों सुनी। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक बच्चों के साथ बातचीत की शुरूआत उनके परिचय के साथ की । इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डी. शिवकुमार और राज्यपाल थावर चंद गहलोत भी मौजूद रहे।

स्त्री-विमर्श ने स्त्रियों को उनके वजूद का अहसास कराया

आंकड़े बताते है कि स्त्री विकास के तमाम दावों के बावजूद अधिक खतरों से घिर गई है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की असुरक्षा शामिल है। दरअसल जो स्त्रियां लिखती है सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, बल्कि उन तमाम स्त्रियों की कहानी कहती हैं जो अपनी बात कह नहीं पाती है आज स्त्रियों का व्यापक स्तर पर लिखना वृहद सामूहिक चेतना और बहनाये की अभिव्यक्ति है। इस एका भाषा में बड़ी ताकत होती है जब कवि माया एंजेलु कहती है स्टिल आई राइज तो वे सिर्फ अपने देश की अश्वेत स्त्रियों की बात नहीं कर रही होती है, बल्कि उनकी कविता हर उस स्त्री की आवाज बन जाती है जिसे तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। पिछले बीस सालों में स्त्रियों की दुनिया बहुत बदली है। हर क्षेत्र में उनकी भूमिका में बदलाव है और उनकी स्थितियां बदल गई है स्त्रियों की सोच बदली है, लेकिन उनके प्रति समाज और परिवार के रवैये में आशिक बदलाव ही दिखाई दे रहे हैं। महिला सशक्तीकरण महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। नब्बे के दशक की शुरूआत का किस्सा मेरी चचेरी बहन की शादी जय हो रही थी, मुंबई के एक पढ़े-लिखे बैंकर से मेरी बहन जमशेदपुर में एक स्कूल में पढ़ाती थीं। शादी तय होने के बाद जब उनसे मिलने गई तो खुश हो कर बोली, अब मैं मुंबई में काम करूंगी। दो दिन बाद बहन का फोन आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। उदास थी। उसके होने वाले पति का मानना था कि शादी के बाद उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका काम होगा ड्डे और बीमार सास-ससुर को संभालना उनके खाने पीने दवा-दारू का ख्याल रखना। बहन की आंखों से आंसू झरने लगे, मैं कोई बगावती लड़की नहीं हूँ, पर हमें नौकरी नहीं छोड़ना चाहती मेरा वजूद मेरी नौकरी से बनता है। दरअसल यहां वजूद मुख्य है। निःसंदेह स्त्री-विमर्श ने स्त्रियों को उनके वजूद का अहसास कराया है। रिश्ता तोड़ने की मेरी सलाह का पूरे परिवार ने मजाक बना दिया। बहन की जिंदगी टॉक्सिक होनी ही थी तीस साल में खुद न जाने क्या-क्या रोग पास बेटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई सो अलग बहन की बेटी को मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ा अपने लिए तो लड़ी ही अपनी मां के लिए भी लड़ी बीस सालों में लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई जिसने दबने अथवा चुप रहने को थैंक यू कहकर पीछा छुड़ा लिया और अपनी आवाज को बुलंदी दी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com